WWW.Kanchanujala.in

हिन्दी दैनिक

kanchanujala14@gmail.com

कंचन उजाला

तापसी पन्नू की फिल्म एनाबेल के शूटिंग पूरी अभिनेत्री ने दिया हिंट

लखनऊ से प्रकाशित

सच्चाई के साथ

वर्षः 01 अंक : 287 | लखनऊ, बुधवार, 07 अक्टूबर, 2020 | पृष्ठ- 6 | मूल्य - 1 रुपये

कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा

अब तक साढ़े 56 लाख से अधिक हुए स्वस्थ

नयी दिल्ली, एजेंसी। देश में गत तीन दिन से कोरोना की बीमारी से मुक्ति पाने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा हुआ है जबकि संक्रमण के नये मामलों में लगातार कमी आयी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 75,787 कोरोना संक्रमितों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ , जिन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी। देश में अब तक 56,62,490 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसी अवधि में 61,267 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद संक्रमण का आंकड़ा 66,85,082 हो गया। इससे पहले रविवार को 82,259 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए थे जबकि संक्रमण के 75,829 मामले आये थे। इसी तरह सोमवार को रिकवरी और संक्रमण के मामलों की संख्या क्रमशः 76,737 और 74,442 रही। पिछले 24 घंटों में 884 संक्रमित अपनी जान गंवा बैठे और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,03,569 हो गयी है। कोरोना संक्रमण के नये मामलों में कमी आने के कारण सक्रिय मामले 15,404 घटकर 91,90,23 हो गये। देश में अभी सक्रिय मामलों का प्रतिशत 13.75 और रोगमुक्त होने वालों की दर 84.70 प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर 1.55 फीसदी रह गयी है। कोरोना महामारी से सबसे अधिक

प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 3001 कम होकर 2,52,721 रह गये हैं जबकि 263 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 38,347 हो गयी है। इस दौरान 12,982 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 11,65,585 हो गयी। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या में 97 की कमी आयी है और राज्य में अब 1,15,496 सक्रिय मामले हैं। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 9370 पर पहुंच गया है तथा अब तक 5,22,846 लोग स्वस्थ हुए हैं। आंध्र प्रदेश में इस दौरान मरीजों की संख्या सबसे अधिक 3340 कम होने से सक्रिय मामले 51,060 रह गये। राज्य में अब तक 6019 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल 6,66,433 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस दौरान 1361 मरीज कम हुए हैं जिससे सक्रिय मामले 45,024 हो गये हैं तथा इस महामारी से 6092 लोगों की मौत हुई है जबकि 3,66,321 मरीज ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या 45,881 हो गयी है तथा 9846 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में अब तक 5,69,664 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं। केरल में सक्रिय मामले 84,958 हो गये तथा 859 लोगों की मौत हुई है जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,49,111 हो गयी है। ओडिशा में सक्रिय मामले 28,006 हो गये हैं और 924 लोगों की मौत हुई है जबकि रोगमुक्त लोगों की संख्या 2,06,400 हो गयी है। राजधानी दिल्ली में इस दौरान सक्रिय मामले 1673 कम होने से यह संख्या 23,080 हो गयी है। वहीं संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 5542 हो गयी है तथा अब तक 2,63,938 मरीज रोगमुक्त हुए हैं।

नई शिक्षा नीति लागू करने में एनसीईआरटी की भूमिका महत्वपूर्णः डॉ निशंक

नयी दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली शिक्षा और शिक्षक-शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और इस नीति को लागू करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वह नए पाठ्यक्रम,पाठ्यपुस्तकों और स्कूल के अन्य पहलुओं पर दिशानिर्देश देगी। डॉ .निशंक ने एनसीईआरटी के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि किसी भी संस्था की वास्तविक पहचान उसके भवन से नहीं होती है बल्कि उसके कार्यों से होती है और एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षिक उपलब्धियों के द्वारा ही अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होनें एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. हृषिकेश सेनापति को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएँ दी और कहा कि एनसीईआरटी के अनिवार्य कार्यों में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए निरंतर शोध करने के साथ साथ बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए उपयोगी शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है। संस्थान ने पिछले पाँच दशकों से भी अधिक समय में इन तीनों ही क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएं हैं जिसमें स्कूली शिक्षा और शिक्षक-शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाने की संस्तुति की गई है। इस नीति को लागू करने में एनसीईआरटी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसे लागू करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई जाएगी जो नए पाठ्यक्रम,पाठ्यपुस्तकों और स्कूल के अन्य पहलुओं पर दिशानिर्देश देगी।

हाथरस गैंगरेप मामला

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें रेप के सबूत नहीं मिलने का जिक्र

नयी दिल्ली, एजेंसी। हाथरस गैंगरेप मामले की हाईलेवल जांच की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने कोर्ट में फोरेंसिक रिपोर्ट सौंपी, उसमें रेप के सबूत नहीं मिलने का जिक्र है। वहीं, चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने पिटीशनर की वकील इंदिरा जयसिंह से कहा, हाथरस की घटना भयानक और चौंकाने वाली थी। हम नहीं चाहते कि बार-बार दलीलें दोहराई जाएं। आपको इसलिए सुन रहे हैं, क्योंकि यह असाधारण मामला है। हम सुनिश्चित करेंगे कि जांच सही तरीके से हो। कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? एफिडेविट देकर बताएं। इस मामले में अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार

की तरफ से कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया। इसमें कहा गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट को खुद भी सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए। पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया, क्योंकि दिन में हिंसा भड़कने की आशंका थी। इंटेलीजेंस इनपुट मिला था कि इस मामले को जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है और पीड़ित के अंतिम संस्कार में लाखों प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं। एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि हाथरस मामले में सरकार को बदनाम करने के लिए नफरत भरा कैंपेन चलाया गया। अब तक की जांच में पता चला है कि कुछ लोग अपने हितों के लिए निष्पक्ष जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। उधर, यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई स्थ्ढ्ढञ्ज ने पीड़ित के गांव बुलगढ़ी में वारदात वाली जगह का जायजा लिया। स्थ्ढ्ढञ्ज बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इस मामले की हाईलेवल जांच की अर्जी लगाने वाले सोशल एक्टिविस्ट सत्यम दुबे, वकील विशाल ठाकरे और रुद्र प्रताप यादव ने अपील की है कि इस केस की जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज या फिर हाईकोर्ट के जज से करवाई जाए।

त्योहारी मौसम में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए एसओपी जारी

नयी दिल्ली, एजेंसी। अक्टूबर से दिसंबर तक देशभर में कई त्योहार मनाये जाते हैं और कोरोना वायरस कोविड-19 के इस संक्रमण काल में बड़े स्तर पर लोगों के जमावड़े से संक्रमण के फैलने का खतरा काफी बढ़ जायेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने त्योहारी मौसम के लिए आज नये दिशानिर्देश यानी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में प्रशासन तथा आयोजनकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश देने के साथ ही आयोजन के दौरान कोरोना संक्रमण के प्रसार से बचाव के उपायों और आयोजन के दौरान किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि होने की दशा में किन निर्देशों का पालन करना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी कंटेनमेंट जोन में कोई भी आयोजन नहीं हो सकता है।

मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती:सुप्रीमकोर्ट

नयी दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करने के मामले में मंगलवार को कहा कि मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती। मातृभाषा के माध्यम से मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना-लिखना सीखना बच्चे के लिए सबसे अच्छी नींव है। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, ÷हमें पता होना चाहिए कि नींव के लिए बच्चे को मातृभाषा के माध्यम से सीखना जरूरी है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करने के जगनमोहन रेड्डी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी है। आंध्र सरकार सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने दलील दी कि मातृभाषा से समझौता नहीं किया जा रहा है। गरीब छात्र अंग्रेजी माध्यम के लिए भारी शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते। राज्य में 96 प्रतिशत माता-पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि तेलुगु के लिए हर मंडल में ऐसा एक स्कूल है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका पर अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अप्रैल में जगनमोहन रेड्डी सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया था।

वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे कोयला घोटाला में दोषी करार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को दोषी ठहराया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने झारखंड के कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में दिलीप रे को आपराधिक साजिश का दोषी पाया। दिलीप रे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थे। रे के अलावा, कोयला मंत्रालय के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी- प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम भी दोषी पाए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पूर्व सलाहकार (प्रोजेक्ट्स) और इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल भी दोषी पाए गए हैं।

शाहजहांपुर में पिता ने नाबालिग पुत्री की हत्याकर किये टुकड़े

शाहजहांपुर, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के सिधौली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना उस समय सामने आई जब एक पिता ने अपने पुत्र के साथ मिलकर नाबालिग पुत्री को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि सिधौली क्षेत्र के सुहेली गांव निवासी एक पिता को अपनी पुत्री पर अवैध संबंधों का शक था। पिता को सूचना मिली कि उसकी नाबालिग पुत्री गर्भवती हो गई है। जिससे नाराज होकर पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री को मौत के घाट उतार दिया। पिता ने अपनी पुत्री की हत्या इतनी दर्दनाक तरीके से की। उसने अपनी बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया शव को ठिकाने लगा दिया। पूरे गांव में बेटी के लापता होने की अफवाह उड़ा दी। मामला पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की।

पचास फीसदी दर्शक क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमाघर खुलेंगे:जावडेकर

नयी दिल्ली, एजेंसी। कोराना महामारी के कारण कई महीनों से बंद पड़े सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में आज सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मानक प्रक्रिया जारी की। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव और सलाह के अनुसार मानक प्रक्रिया जारी की गई है जिसमें 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ सिनेमाघर खुल सकेंगे। मानक प्रक्रिया के अनुसार हॉल में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। हॉल और सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों के बीच 6 फीट की दूरी , हॉल और सार्वजनिक क्षेत्र में मास्क लगाना , प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर टेम्परेचर की जांच करना और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि सभी सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रसारण से पहले और इंटरवेल में कोरोना को लेकर जागृति वाली एक मिनट की फिल्म या उद्घोषणा दिखाना अनिवार्य होगा। फिल्म के दो शो के बीच में आवश्यक अतंराल हो ताकि हॉल को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जा सके। उन्होने कहा सिंगल स्क्रीन वाले हॉल में टिकट खिड़कियों की संख्या को बढ़ाना होगा, टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन मोड को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल में सिर्फ पैकड फूड ही बेचा जा सकेगा। साथ ही हॉल में 23 से 25 डिग्री तापमान बनाए रखना होगा। हर दर्शक का टेंपरेचर मापा जाएगा उसके बाद ही उसे एंट्री दी जाएगी। सिनेमा हॉल में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सभी नियमों का पालन करना होगा जिसमें मास्क, ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। मंत्रालय के मानक प्रक्रिया के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सिनेमाघर नहीं खोले जा सकेंगे। राज्य सरकारें इन उपायों के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों में पचास फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी थी।

बिहार में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस

भाजपा 121, जदयू 115 और मांझी की पार्टी हम 7 सीटों पर लड़ेगी

नयी दिल्ली, एजेंसी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही ऊहापोह के बीच भाजपा और जदयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि हम लोगों का एनडीए गठबंधन है और इसमें हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। ऐलान नहीं किया गया था। जदयू को 122 सीटें दी गई हैं। हम पार्टी को इसी में 7 सीटें दी गई हैं। भाजपा के खाते में 121 सीटें हैं और वीआईपी को इन्हीं सीटों में से हिस्सा दिया जाएगा। उन्होंने कहा- कोरोना का जो प्रकोप दुनिया में हुआ है। हम लोगों ने बिहार में इसके लिए बहुत काम किया है। बिहार में 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच हुई हैं, देश के एवरेज से 3 हजार ज्यादा हैं। मृत्यु दर भी बिहार में कम है। ठीक

होने वालों की संख्या 93 फीसदी से ज्यादा है। इधर, एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और दूसरी ओर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान सोशल मीडिया पर नीतीश को चुनौती दे रहे थे। चिराग ने ट्वीट किया कि अगली सरकार बनते ही सात निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा। दरअसल, चिराग का निशाना नीतीश पर था, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में 7 निश्चय का वादा किया था। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों में सरकार बनने पर किए जाने वाले कामों का जिक्र था। हाल ही में नीतीश ने कहा कि उन्होंने इन 7 निश्चय पर बहुत काम किया है और काफी काम बाकी है। इस बार भी वो 7 निश्चय लेकर जनता के बीच जाएंगे। इससे पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश ने कहा कि मैं प्रवासी शब्द का पक्षधर नहीं हूं। कोई कहीं जाता है तो उसे प्रवासी कहना ठीक नहीं है। बिहार में क्या दूसरे राज्यों के लोग नहीं हैं। क्या केरल या महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं हैं ? बिहार के लोग जो बाहर गए थे, हमने एक-एक से संपर्क किया। 21 लाख लोगों को एक-एक हजार रुपए की सहायता दी। उन्होंने कहा- हम मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम करेंगे। और, किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। किसी को अगर कुछ कहने में आनंद आता है, तो बोलता रहे।

आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय चिकित्सकीय प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी

नयी दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय चिकित्सकीय प्रबंधन प्रोटोकॉल आज जारी किया। डॉ. हर्षवर्धन ने आज कहा कि चिकित्सकीय अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि कोरोना वायरस से बचाव में अश्वगंधा,लौंग और गिलोय जैसे आयुर्वेदिक औषधियां काम आती हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सकीय प्रबंधन प्रोटोकॉल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और सीएसआईआर के अनुसार अद्यतन किया गया है। इसमें कोविड-19 के बचाव के लिए स्वयं की देखभाल संबंध दिशानिर्देश हैं। प्रोटोकॉल में कहा गया है कि कोविड-19 से बचाव के लिए शारीरिक दूरी,श्वसन संबंधी सफाई और हाथों की स्वच्छता के अलावा मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ ही एक चुटकी हल्दी और नमक को गर्म पानी में डालकर गरारे कराने चाहिए। त्रिफला को पानी में उबालकर पानी में यष्टीमधु यानी मुलेठी को भी उबालकर उस पानी से गरारे किये जा सकते हैं। अणु तेल या शादबिंदु तेल या तिल का तेल या नारियल का तेल की बूंदें नाक में डाली जा सकती हैं। इनके अलावा गाय के घी को भी दिन में एक या दो बार नाक में डालना चाहिए, खासकर जब घर से बाहर जाना हो और बाहर से घर लौटे हों। यूकेलिप्टस के तेल, अजवायन या पुदीने को पानी में डालकर दिन में एक बार भाप लेना चाहिए। कम से छह से आठ घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए। व्यायाम करना चाहिए और योग प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।

बॉलीवुड में ड्रग्स मामला

रिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी

नयी दिल्ली, एजेंसी। सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) 14 दिन और बढ़ा दी है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट कल फैसला सुना सकती है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद एक्ट्रेस ने हाईकोर्ट में अपील की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया के साथ उनके भाई शोविक और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जियों पर भी हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। एनसीबी ने रिया और शोविक की जमानत का विरोध किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा है कि रिया और शोविक ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं और कई हाई सोसाइटी लोगों और ड्रग्स सप्लायर्स से जुड़े हैं। इन पर धारा 27 लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एनसीबी ने कहा कि रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है। उन्होंने माना कि ड्रग्स खरीदने के लिए सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शोविक से कहा था। एक्ट्रेस के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा था कि रिया के सुशांत की लाइफ में आने से पहले ही वे ड्रग्स लेते थे। सुशांत को ड्रग्स की लत थी। यह बात 3 एक्ट्रेस कह चुकी हैं। रिया की तरह ही श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने कहा है कि सुशांत 2019 से पहले से ड्रग्स लिया करते थे।

राजस्थान का थानागाजी गैंगरेप केसः चार दोषियों को उम्रकैद

राजस्थान, एजेंसी। राजस्थान में अलवर जिले के थानागाजी गैंगरेप केस में मंगलवार को कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। 4 को उम्रकैद तो घटना का वीडियो वायरल करने वाले पांचवें आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि गैंगरेप की यह वारदात द्रौपदी के चीरहरण जैसी है। इसमें सजा ऐसी होनी चाहिए कि दुष्कर्म की घटनाओं की अमर बेल (लगातार हो रही घटनाओं) को काटा जा सके। यह वारदात 26 अप्रैल 2019 को दिनदहाड़े हुई थी। इसमें पति के सामने ही पत्नी के साथ गैंगरेप किया गया। दोषियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था। इसके वायरल होने के बाद 2 मई यानी 6 दिन बाद थानागाजी थाने में इसका केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने चार दोषियों इंद्राज, अशोक, छोटेलाल और हंसराज को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन चारों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वीडियो वायरल करने के दोषी मुकेश को 5 साल की सजा मिली। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 16 दिन बाद ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। इस मामले में नाबालिग भी अपराधी है। उसके खिलाफ अलवर के जुवेनाइल बोर्ड में सुनवाई चल रही है। थानागाजी के रहने वाले दंपती बाइक पर जा रहे थे। तभी पांच युवकों ने उनका पीछा करके उन्हें रोक लिया। इसके बाद दोषी पति-पत्नी को जबरन जंगल ले गए। वहां महिला के साथ पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद पीड़ित पति-पत्नी थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने चुनाव में व्यस्त होने की बात कहकर केस दर्ज नहीं किया।

कृषि कानूनों पर कांग्रेस का विरोध

लंबी गहमागहमी के बाद राहुल गांधी 4 ट्रैक्टर संग हरियाणा में हुए दाखिल

कुरुक्षेत्र, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब-हरियाणा बार्डर से हरियाणा में दाखिल हो गए हैं। राहुल ट्रैक्टर यात्रा के साथ पिहोवा अनाजमंडी में रैली में पहुंचे। रैली में वह किसानों, आढ़तियों और मजदूरों को संबोधित करेंगे। रैली में राहुल गांधी को हरियाणा पगड़ी देकर सम्मानित किया गया। इससे पहले राहुल गांधी ने काफी देर तक चली गहमागहमी के बाद चार ट्रैक्टरों के संग हरियाणा में प्रवेश किया। उनके ट्रैक्टर पर हरियाणा में प्रवेश को लेकर विवाद और टकराव पैदा हो गया था। पुलिस राहुल को पैदल पंजाब से हरियाणा में आने को कह रही थी, लेकिन राहुल ट्रैक्टर पर ही आने को अड़े हुए थे। वह करीब 25 मिनट से पंजाब सीमा में मारकंडा पुल पर खड़े रहे। अब पुलिस से सहमति बन गई। राहुल गांधी के ट्रैक्टर

को पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और बाद में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा चलाकर हरियाणा में प्रवेश किया। ट्रैक्टर यात्रा का पिहोवा, कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ट्रैक्टर चला रही हैं। ट्रैक्टर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सवार थे। ट्रैक्टर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सवार थे। शहर से गुजरते हुए राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा पिहोवा अनाजमंडी पहुंची। वहां वहां राह किसानों, आढ़तियों और मजदूरों को संबोधित करेंगे।

जिन जनपदों में कोविड-19 के 50 से 100 मामले प्रतिदिन, ऐसे जनपदों पर विशेष ध्यान दिया जाए

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जनपदों में कोविड-19 के 50 से 100 मामले प्रतिदिन मिल रहे हैं, ऐसे जनपदों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बचाव एवं उपचार कार्य पूरी सक्रियता से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जनपद लखनऊ और कानपुर नगर पर विशेष ध्यान देते हुए रिकवरी दर को बेहतर किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा जनपद लखनऊ व कानपुर नगर की स्थिति की गहनता से मॉनिटरिंग की जाए तथा इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश देते हुए इसका संचालन पूरी सक्रियता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जाए। उन्होंने स्वच्छता व सेनिटाइजेशन का कार्य सतत जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि एन्टीलार्वा रसायनों का नियमित छिड़काव भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो बजट खेती, जिसे अब भारतीय प्राकृतिक खेती कहते हैं, को बढ़ावा दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई असुविधा न हो तथा किसानों की उपज का भुगतान 72 घण्टे में उनके बैंक खाते में अन्तरित कर दिया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को पराली न जलाने के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए बताया जाए कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए। राजस्व वृद्धि के लिए पूरी सक्रियता से प्रयास किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया जाए। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, राहत आयुक्त संजय गोयल, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लक्ष्य की महिला कमांडरों की गिरफ्तारी संविधान का अपमान हैः लक्ष्य

लखनऊ, संवाददाता। लक्ष्य की महिला कमांडरों जो हाथरस की घटना के विरोध में परिवर्तन चौक लखनऊ पर कैंडल मार्च के लिए गई थी और जिसकी सूचना दिनांक 30 सितम्बर को जिला अधिकारी व पुलिस कमिश्नर को दे दी गई थी इसके बावजूद लक्ष्य की महिला कमांडरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह शासन प्रशासन की खुलमखुल्ला अंधेरगर्दी है जवाब दें, उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वे उन पुलिस अधिकारीयों के खिलाफकड़ी से कड़ी कार्यवाही करें जिन्होंने लक्ष्य की महिला कमांडरों को गैरकानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था और उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया है ताकि समाज का सरकार पर विश्वास बना रहे।

हाथरस की घटना के विरोध में एकत्र हुए सफाई कर्मचारी, दी श्रद्धांजलि

लखनऊ, संवाददाता। हाथरस की घटना के विरोध में लखनऊ के सफाई कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लालबाग स्थित सुपंच सुदर्शन वाटिका पर किया। इसमें शहर के अलग-अलग इलाकों से सफाई कर्मचारी एकत्र हुए। मृतका के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सफाई कर्मचारी नेता नरेश बाल्मीकि का कहना है सभी सफाई कर्मचारियों ने सुबह अपने-अपने इलाकों में सफाई की और काम खत्म होने के बाद श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। दोषियों पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र नगर आयुक्त को दिया गया है। बता दें सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड पर आज सुनवाई होगी। जिसमें हाथरस जिले में अनुसूचित जाति की युवती की हत्या मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल से कराने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत मंगलवार यानी आज सुनवाई करेगी।

हाथरस रेप केस पहचान उजागर पर स्पेशल सीजेएम कोर्ट में वाद दायर

लखनऊ, संवाददाता। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने हाथरस बलात्कार एवं हत्या मामले में फेसबुक तथा ट्विटर पर पीडिता का नाम लिए जाने, उसके नाम से ट्विटर पर विभिन्न हैशटैग चलाये जाने, पीडिता के फोटो तथा विडियो शेयर किये जाने आदि के संबंध में थाना गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने के बाद स्पेशल सीजेएम कोर्ट कस्टम लखनऊ में वाद दायर किया है। नूतन ने वाद में कहा कि पीडिता की फोटो के साथ ही उसकी पहचान को उजागर करते हुए कई विडियो यूट्यूब पर डाले गए हैं. धारा 228ए आईपीसी के अनुसार रेप पीडिता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय अपराध है. सुप्रीम कोर्ट ने भी निपुण सक्सेना केस में स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी स्थिति में रेप पीडिता की पहचान नहीं उजागर की जाये।

अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगा रही है सरकारः सपा

लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी से एमएलसी सुनील सिंह साजन ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा योगी सरकार में कानून का कोई राज नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अपराधी व्यापारी को लूट रहे है। योगी सरकार कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रही है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रही है। उन्होंने हाथरस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को सजा तो दे नहीं पा रही है। झूठे विपक्षी पार्टियों पर दंगा भड़काने का आरोप लगा रही है। सिंह ने का कि जो लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे है। उनके खिलाफसरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। बता दें कि हाथरस कांड को लेकर सरकार ने विपक्षी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए है।

कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफएमपी-एमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने मानहानि के मामले में हाजिर नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट में यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मानहानि के मामले में अजय कुमार लल्लू के खिलाफपरिवाद दर्ज कराया था। अदालत ने उनके परिवाद पर संज्ञान लेते हुए लल्लू को बतौर अभियुक्त जरिए समन तलब किया था। लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे थे। लिहाजा उनके खिलाफगिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।

सीआईसी रिक्ति, मुख्य सचिव ने कहा सुरेश खन्ना, रामगोविंद से संपर्क किया

लखनऊ, संवाददाता। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को भरे जाने के संबंध में दायर याचिका में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश आर के तिवारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया कि राज्य सरकार प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने का हरसंभव प्रयास कर रही है, श्री तिवारी ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विपक्ष के नेता राम गोविन्द चौधरी तथा मंत्री सुरेश खन्ना की 03 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर श्री चौधरी तथा श्री खन्ना को कोई 02 तारीख बताने हेतु पत्र भेजा जा चुका है ताकि यह मीटिंग की जा सके. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा कर लिया जायेगा, नूतन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए यथाशीघ्र रिक्ति भरने के निर्देश देने की प्रार्थना की है।

रिक्शा चालक को अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर, घायल

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ आलमबाग थाना क्षेत्र में मवैया पुल के नीचे तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। जहां सोमवार रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे रिक्शा चालक घायल हो गया। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने ही मौके पर पहुची पुलिस ने रिक्शा चालक को ट्रामा सेंटर पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक घायल युवक आलमबाग से चारबाग की तरफई रिक्शा चलाने का काम करता है।

अवैध खनन में छह गिरफ्तार, जेसीबी सहित छह वाहन सीज

बाराबंकी, संवाददाता। पुलिस ने बेलहरी गांव में छापेमारी कर अवैध मिट्टी खनन में लगी जेसीबी सहित पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली बरामद की हैं। मौके से ठेकेदार सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जेसीबी ऑपरेटर भाग निकला। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बेलहरी गांव में बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा था। सोमवार रात करीब 12 बजे दरियाबाद थाने व अलियाबाद चौकी के पुलिस बल ने दबिश देकर जेसीबी, पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में ले लिया। साथ ही बबुआपुर निवासी सतीश वर्मा, अयोध्या के मवई चौराहा निवासी रिंकू गुप्ता, जवसापुत थाना पटरंगा निवासी उमेश कुमार, मवई के कुशहरी निवासी नसीम, पटरंगा के बाकरपुर निवासी अन्नू वर्मा और अंसदरा थाने के छोटी जमोली गांव निवासी रामसमुझ को गिरफ्तार कर लिया।

हाथरस कांड पर बोले मोहसिन रजा, प्रदेश में हिंसा कराने की शाजिश में पीएफआई

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हाथरस कांड में का जिक्र करते हुए कहा कि देश व प्रदेश में आतंकवाद को फैलाने में राजनीतिक दल पीएफआई को समर्थन दे रहे है। वो देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते है। भारत सरकार से मांग करता हूं किसिमी की तरह ही जांच कर पीएफआई को भी आतंकी संगठन घोषित कर बैन लगाया जाए। जांच के बाद संगठन से जुड़े सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बता दें कि मोहसिन रजा ने कहा कि हाथरस प्रकरण में पीएफआई की भूमिका निकल कर आई है। वो इलाके में जातिगत दंगे करवाने की कोशिश में था। मंत्री ने आगे कहा कि जो भी राजनीतिक दल पीएफआई को समर्थन दे रहे हैं वो देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जांच कर पीएफआई को भी आतंकी संगठन घोषित कर बैन लगाया जाए। गौरतलब है कि हाथरस गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को साजिश का दावा किया था। जिसके बाद से एजेंसियाँ चौकन्नी हो गई हैं और हाथरस आने-जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मथुरा में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों का संबंध पीएफआई से बताया जा रहा है। इनमें एक मल्लापुरम का रहने वाला है, जबकि तीन अन्य मुजफ्फरनगर, बहराईच और रामपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन चारों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य बरामद किया है। फिलहाल हाथरस आने जाने वालों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है।

दंगा भड़काने की साजिश का आरोप सही या चुनावी चाल, वक्त बताएगाः माया

लखनऊ, संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा विपक्ष पर जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरोप सही है या फिर चुनावी चाल, यह तो वक्त ही बताएगा। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, हाथरस काण्ड की आड़ में विकास को प्रभावित करने के लिए जातीय व साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का विपक्ष पर लगाया गया यूपी सरकार का आरोप सही या चुनावी चाल, यह समय बताएगा, किन्तु जनमत की मांग है कि हाथरस काण्ड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर सरकार ध्यान केन्द्रित करे तो बेहतर। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, वैसे हाथरस काण्ड को लेकर पीड़िता के परिवार के साथ जिस प्रकार का गलत व अमानवीय व्यवहार किया गया उससे देश भर में काफी रोष व आक्रोश है। सरकार अब भी गलती सुधारे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गंभीर हो वरना जघन्य घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हाथरस में एक दलित लड़की से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसकी मौत के मामले को लेकर जातीय और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग विकास में बाधा डालने के लिए ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल इसे योगी द्वारा अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दे रहे हैं। बहरहाल, सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप में डेढ़ दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

लोकदल निजीकरण के विरोध में संगठनों के आंदोलन के निर्णय का पुरजोर समर्थन करता हैः लोकदल

लखनऊ, संवाददाता। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा है कि पूर्वांचल में विद्युत विभाग के निजीकरण का विरोध हो रहा है लोकदल पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करती है चन्द कॉरपोरेट घरानों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाने के लिये न सिर्फ बिजली बल्कि कोयला, तेल, रेल, बैंक, बीमा, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा आदि सहित सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार का विकास का मॉडल राष्ट्रीय सम्पत्ति को बेचकर उसे बर्बाद करने का मॉडल है जो राष्ट्रवाद के नाम पर बढ़-चढ़ कर प्रचारित किया की जा रहा है जिसका कि अब पूरी तरह भंडाफोड़ हो चुका है।लोकदल सरकार की इस तरह की निजीकरण की नीति की कड़ी निन्दा करता है। कर्मचारी आन्दोलन को भी इससे विशेषरूप से सावधान रहने की जरूरत है।बिजली क्षेत्र में घाटे का तर्क देकर सरकार द्वारा निजीकरण करने के पीछे एक कारण पावर परचेज घोटाला भी है। बिजली का लागत मूल्य काफी कम होने के बावजूद निजी बिजली उत्पादकों के प्लांट पूर्ण क्षमता पर चलवाकर उच्च दरों पर बिजली खरीदी जाती है तथा सस्ती बिजली पैदा करने वाले सरकारी बिजली उत्पादन केन्द्रों का उत्पादन, थर्मल बैकिंग के नाम पर, प्रतिबन्धित करने व अनुरक्षण हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध न कराने की खबरें आती रहती हैं। गलत और दीर्घकालीन अनुबन्ध के कारण वर्तमान में 2.44 प्रति यूनिट में उपलब्ध सौर बिजली, गुजरात सरकार को 15 प्रति यूनिट की दर से अनिवार्यतः खरीदनी पड़ रही है। कॉरपोरेट घरानों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाने के लिये ही इस तरह के अनुबन्धों को सख्ती से लागू करने हेतु विद्युत संशोधन विधेयक-2020 में का प्राविधान किया गया है। श्री सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार का यह फैसला हैरानी भरा है कि थर्मल व सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारी मुनाफा कमाने वाले निजी निवेशकों से सार्वजनिक बैंकों द्वारा सरकारी नीति के तहत उपलब्ध कराये गये ऋण की वसूली की प्रभावी व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे लाखों करोड़ का ऋण बट्टेखाते (एनपीए) में डाला जा रहा है। श्री सिंह ने आरोप लगाया है कि बिजली क्षेत्र में घाटे का तर्क देकर सरकार द्वारा निजीकरण करने के पीछे एक कारण पावर परचेज घोटाला भी है।

चिनहट में बंद मकान समझकर चोरों ने लगा दी छलांग, मचा हड़कंप

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी के चिनहट थाना क्षेत्र के विकल्प खंड 3 में चोरों ने बंद पड़ा मकान समझकर छलांग लगा दी। इस दौरान घर के मालिक मौजूद थे। खटपट की आवाज सुनकर उन्होंने देखा तो चोरों ने उन पर चाकू से धावा बोल दिया। चोर आते समय सीसीटीवी का डीवीआर अपने साथ लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस एफआईआर दर्ज करने के साथ ही जांच कर रही है। मामला थाना क्षेत्र के विकल्प खंड तीन का है। बीती रात चोरों ने खाली मकान समझ कर रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर के घर में छलांग लगा दी। इस दौरान फूड इंस्पेक्टर और उनका परिवार घर के अंदर ही सो रहे थे। चोरों द्वारा खटपट की आवाज सुनने पर उनकी नींद टूट गई और वह देखने आ गए। चोरों ने अपने बचाव में चाकू से रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर धावा बोल दिया जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जब परिवार के आने लोग भी मौके पर आ गए तो चोर मौके से फरार हो गए वह अपने साथ घर में लगा सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए।

बिजली पानी की हो रही समस्या की जिम्मेदार आरएसएस-भाजपा सरकारः एआईपीएफ

लखनऊ, संवाददाता। प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण हो रही आम जनता को बिजली और पानी की समस्याओं की जिम्मेदार आरएसएस और भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार है. यह सरकारें कारपोरेट हितों के लिए सार्वजनिक संपदा के निजीकरण को करने की हठधर्मिता पूर्ण नीतियां लागू कर रही हैं. सरकारें बिजली, रेल, तेल, कोयला, बीएसएनएल, बैंक, बीमा जैसी जो भी राष्ट्रीय संपदा थी उसे हर हाल में बेचने पर आमादा है. इसलिए इनकी रक्षा के लिए चलाया जा रहा बिजली कर्मचारियों का आंदोलन राष्ट्रीय हितों का आंदोलन है. आइपीएफ जनता को हो रही तकलीफों को लेकर चिंतित है और सरकार से अपील करती है कि वह अपनी हठधर्मिता से पीछे हटकर निजीकरण के फैसले को वापस लें ताकि आम जनता को हो रही परेशानियों से उसे निजात मिल सके. प्रेस को आज जारी बयान में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के नेता दिनकर कपूर व वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर दुर्गा प्रसाद ने यह बातें कहीं. उन्होंने कहा कि आईपीएफ व वर्कर्स फ्रंट के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के साथ हैं और जनता से भी अपील करता है कि वह सरकार पर दबाव डालें कि वह जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए पहल करें। उन्होंने कहा कि आरएसएस-भाजपा की सरकार निजीकरण के लिए विद्युत् संशोधन विधेयक 2020 लाने पर आमादा है. लेकिन प्रदेश में तो इससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के पूर्वांचल विद्युत् वितरण निगम के निजीकरण का फैसला कर लिया गया. इन नीतियों से किसानों, मध्यवर्ग और आम जनता को बेहद महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा और समाज का गरीब गुरबा तो बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का बिजली क्षेत्र के घाटे का तर्क भी बेमानी है क्योंकि जो मौजूदा घाटा है उसमें करीब तीस हजार करोड रुपए तो अकेले सरकार का ही बकाया है यदि उसे ही चुकता कर दिया जाए तो एक हद तक घाटे को कम किया जा सकता है. लेकिन सरकार यह देने को तैयार नहीं है. हद तो यह है कि उत्तर प्रदेश में बेहद सस्ती दर पर बिजली पैदा करने वाली अनपरा जैसी इकाइयों को थर्मल बैकिंग यानी बिजली उत्पादन को बंद करने के फैसले किए जाते हैं और उसी समय बेहद महंगी दर पर कारपोरेट घरानों से बिजली खरीदी जाती है और तर्क दिया जाता है कि हमारा पहले से समझौता है, इसलिए उनसे बिजली खरीदना हमारी मजबूरी है. यह साफतौर पर बड़े भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बिजली का क्षेत्र नो प्रॉफिट नो लॉस पर जनता के बुनियादी अधिकार के बतौर सार्वजनिक क्षेत्र में सृजित किया गया था जिसे आरएसएस-भाजपा की केंद्र व राज्य की सरकार अब बर्बाद करने में लगी है।

लखनऊ में दो पक्षों में दरवाजा लगाने के विवाद को लेकर खूनी रंजिश, छह लोग घायल

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी में सोमवार देर रात दरवाजा लगाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जो खूनी रंजिश में तब्दील हो गई। दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। घटना में छह से अधिक लोग घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटौंजा ले जाया गया, जहां दो की हालत गंभीर देख उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। इंस्पेक्टर इटौंजा ने जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। मामला इटौंजा के परसहिया गांव का है। यहां के निवासी प्रेम ने थाने में दी गई तहरीर में कहा है कि उनके पिता छेटेलाल भाई बबलू पत्नी कृष्णा, भाई सतीश व घर के अन्य लोग बैठे थे। तभी उनके चाचा के बेटे अजय, विजय, गोविंद व अन्य लोग घर में दरवाजा लगाने को लेकर गाली-गलौज करने लगे। जिसका विरोध करने पर लाठी-डंडों ईट-पत्थर से हमला कर दिया। घटना में पिता छेटे-लाल भाई बबलू उनकी पत्नी कृष्णा व अन्य लोग घायल हो गए। उधर, दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि मारपीट से अजय, विजय, गोविंद व अन्य कई लोगों को चोटे आई हैं।

चेहल्लुम से पहले सड़क पर पुलिस फोर्स के साथ पैदल चले ज्वाईन्ट पुलिस कमिश्नर

जेसीपी ने कहा जनता मे सुरक्षा की भावना को जागृत करने के लिए किया गया रूटमार्च

लखनऊ, संवाददाता। कोरोना काल मे पड़ रहे चुहेल्लुम को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने कमर कस ली है। सरकारी गाईड लाईन के अनुसार चेहल्लुम को सुरक्षित माहौल मे शान्तीपूर्ण तरीके से सकुशल सम्पन्न कराने के लिए चेहल्लुम से मात्र दो दिन पहले आज पुराने लखनऊ मे संयुक्त पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा के नेतृत्व मे रूट मार्च कर जनता मे सुरक्षा की भवना को जागृत किया गया। चेहल्लुम से पूर्व जेसीपी के नेतृत्व मे किया गया रूट मार्च आज दोपहर रूमीगेट पुलिस चौकी के पास से शुरू किया गया जो चौक पाटानाला, नख्खास बिल्लौचपुरा ,मंसूरनगर कटरा काजमैन होता हुआ पुराने लखनऊ की तंग गलियों से गुजरा । कड़ी धूम मे पुलिस फोर्स के साथ पैदल चल रहे जेसीपी नवीन अरोड़ा डीसीपी पश्चिम देवेश पाडेय्य एडीसीपी, पश्चिम, एसीपी चौक, एसीपी बाजार खाला , एसीपी कैसरबाग के अलावा पश्चिम क्षेत्र के सभी थाने के इन्स्पेक्टरो के अलावा भारी सख्या मे पुलिस फोर्स सड़क पर चलने वाले लोगो के कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक भी करते हुए देखे गए । सड़क पर जो लोग लापरवाही वश बिना मास्क के नजर आ रहे थे पुलिस के अधिकारी उन लोगो से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेसिग का पालन करने के लिए उन्हे जागरूक भी कर रहे थे। जेसीपी नवीन अरोड़ का कहना था कि रूट मार्च का मकसद जनता मे सुरक्षा की भावना को जागृत करना है उन्हाने कहा कि लोग कानून को अपने हाथ मे कतई न ले उन्होने कहा कि हम जनता की सुरक्षा के लिए दृढ संकल्प है उन्होने चेहल्लुम के मौके पर लोगो से सरकारी गाईड लाईन और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमो का अक्षरशः पालन करने की अपील भी की। आपको बता दे कि 25 मार्च से लागू हुए लाक डाउन के बाद पूरे देश मे सभी धर्मो के धार्मिक कार्यक्रमो पर लगी रोक की वजह से सभी धर्मो के धार्मिक कार्यक्रम प्रभावित हुए है कोरोना वायरस की कोई दवा न होने की वजह से इस घातक बिमारी की रोकथाम के लिए एक मात्र उपाए सोशल डिस्टेंसिग ही माना गया है और किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बिना भीड़ के मुमकिन नही होता है इस लिए सभी धर्मो के भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमो पर अभी भी रोक लगी हुई है। कोरोना वायरस की वजह से इस साल शिया समुदाय का एक भी जुलूस नही निकल पाया 19 रमजान 21 रमजान के जुलूसो के अलावा मोहर्रम के महीने मे भी कोई जुलूस नी निकाला गया । हजरत इमाम हुसैन अ0स0 की शहादत के मौके पर दस मोहर्रम को भी न तो यौमे आशूर का जुलूस ही निकाला गया और न ही कर्बलाओ मे ताजिए दफन करने की ही अनुमति दी गई थी। लोगो को उम्मीद थी कि मोहर्रम तो जैसे तैसे गुजर गया लेकिन हजरत इमाम हुसैन के चेहल्लुम के मौके पर शिया समुदाय के लोगो को जुलूस निकाल कर इमाम हुसैन का गम मनाने का मौका जरूर मिलेगा लेकिन कोरोना वायरस का प्रकोप है कि कम होने का नाम नही ले रहा है।

लखनऊ के दो मुहल्लों में फैला डेंगू, मरीजों की मौतों पर पर्दा,ये लक्षण दिखे तो ऐसे करें बचाव

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ में कोरोना के प्रकोप के बीच डेंगू का दंश बरकरार है। अस्पतालों में हर रोज मरीज भर्ती हो रहे हैं। मगर, कोरोना की आड़ में डेंगू की मौतों पर पर्दा डाला जा रहा है। स्थिति यह है कि शहर के दो सौ मोहल्लों में डेंगू फैला है। मगर, लैब-अस्पताल द्वारा मरीजों की रिपोर्टिंग छिपाई जा रही है। शहर में 950 रजिस्टर्ड नर्सिंग होम हैं। वहीं 650 के लगभग पैथोलॉजी हैं। अगस्त अंत तक सरकारी अस्पताल डेंगू की रिपोर्ट सीएमओ कार्यालय नहीं भेज रहे थे। वहीं अब लोहिया संस्थान, केजीएमयू, पीजीआइ व अन्य सरकारी अस्पताल द्वारा रिपोर्टिंग शुरू कर दी गई है। वहीं निजी सिर्फ छह लैब ही डेंगू के मामले सीएमओ दफ्तर को बता रही हैं। ऐसे में डेंगू की हकीकत पर पर्दा पड़ा हुआ है। करीब 20 दिन पहले चाणक्यपुरी निवासी महिला की इंदिरा नगर के निजी अस्पताल में मौत हो गई। परिवारजनों को अस्पताल में डेंगू बताया। मगर, सीएमओ कार्यालय में अभी तक डेंगू से मृतकों का आंकड़ा शून्य बना हुआ है। ऐसे ही कई मरीजों की डेंगू से मौत हो चुकी है। मगर, किसी की डेथ ऑडिट नहीं की गई है। वहीं, जनवरी से अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 107 ही हुई है। यह हाल तब है जब शहर के 110 वार्डों के दो सौ मोहल्लों में डेंगू की दस्तक है। वहीं नगरीय मलेरिया अधिकारी डॉ. केपी त्रिपाठी के मुताबिक डेंगू के करीब 200 मोहल्ले चिन्हित किए गए हैं। इसमें 35 टीमें एंटीलार्वा छिड़काव कर रही हैं। जैसे ही कोई डेंगू का केस रिपोर्ट होता है। वहां, तत्काल मच्छर रोगी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा सभी लैब व अस्पतालों के डेंगू मरीजों का ब्योरा भेजने का निर्देश दिया गया है। अभी तक डेंगू से मौत की जानकारी नहीं मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की 11 सीएचसी पर डेंगू के लिए बेड रिजर्व किए गए हैं। वहीं लोहिया संस्थान में 20 बेड डेंगू मरीजों के लिए रिजर्व हैं। बलरामपुर अस्पताल में 30 बेड, सिविल अस्पताल में 30 बेड रिजर्व किए गए हैं।

एनपीएस को प्रान एकाउंट में अपडेट कराए डीआईओएसः संजय द्विवेदी

-शिक्षक समस्याओं को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक व उप शिक्षा निदेशक मिलकर वार्ता की

बस्ती। मंगलवार को जिला विद्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल मण्डलीय मंत्री संजय द्विवेदी के नेतृत्व में संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी व उप शिक्षा निदेशक ओमप्रकाश मिश्रा से मिला। श्री द्विवेदी ने कहा कि बस्ती मंडल में एनपीएस अंशदान की कटौती प्राण अकाउंट में अपडेट नहीं हो पा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सेवानिवृत्त पुल शिक्षकों के रिन्यूवल में कठिनाई उत्पन की जा रही है, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। श्री द्विवेदी ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक संतकबीरनगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। रिश्वत लेकर उमरिया, सिरसी , प्रहलादराय बालिका इंटर कॉलेज व हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज में समितियों से तालमेल कर शिक्षकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। नियम-कानून को ताक पर रखकर फैसले ले रहे हैं। शिक्षक नेताओं ने जिला विद्यालय निरीक्षक के भ्रष्टाचार के प्रमाण भी प्रस्तुत किये। श्री द्विवेदी ने बताया कि बस्ती, संतकबीरनगर व सिद्धार्थनगर जनपद के बोर्ड परीक्षा पारिश्रमिक वर्ष 2019 व 2020 के बकाया धनराशि का भुगतान नहीं हो रहा है। वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय भुगतान ना होने से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान व एरियर के प्रकरणों के निस्तारण में भी रिश्वत मांगी जा रही है।

श्री द्विवेदी ने बताया कि मंडल के संत कबीर नगर में 34, सिद्धार्थनगर में 48 व बस्ती के 70 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जूनियर कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को अभी तक निशुल्क पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। जिससे बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान प्रांतीत उपाध्यक्ष मार्कण्डेय सिंह, राम पूजन सिंह, जय प्रकाश मिश्रा, गिरिजानन्द यादव, अजय प्रताप सिंह, आदित्य सिंह, अरुण मिश्रा, मोहिबुल्लाह खान, गुलाब चन्द्र मौर्या, विजय बहादुर सिंह, हरिकेश बहादुर यादव, महेश राम, जय चन्द्र यादव, राम नारायण पांडेय, उदयभान सिंह, विनोद चौरसिया, गोपाल जी सिंह, विनोद उपाध्याय, अरशद जलाल, महेश्वर सिंह, मंगला प्रसाद सहित अन्य मौजुद रहे। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि शिक्षक समस्याओं के निस्तारण के लिए बस्ती, सन्तकबीरनगर व सिद्धार्थनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश भेजा रहा है।

बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया

लखनऊ। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री शिवाकान्त द्विवेदी द्वारा लखनऊ शहर में हो रहे अवैध निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रवर्तन विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं को दिये गये सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 06.10.2020 को निम्नानुसार कार्यवाही की गयी। श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा प्लाट संख्या 5-6 (खसरा संख्या 3989द.मि.), शान्तीनगर, सरोजनीनगर, लखनऊ पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध वाद संख्या 317/2020 योजित किया गया। योजित वाद में विहित प्राधिकारी-श्रीमती ऋचु सुहास द्वारा दिनांक 29.09.2020 को सील किये जाने के आदेश दिये जाने पर अधिशासी अभियन्ता श्री कमलजीत सिंह के नेतृत्व में अवर अभियन्ता-श्री विनोद शंकर सिंह व श्री इम्तियाज अहमद तथा क्षेत्रीय थाना पुलिस बल व प्राधिकरण पुलिस बल की सहायता से सील किया गया।

निजीकरण के विरोध प्रदर्शन में अधिकारियों और कर्मचारियों के जाने के बाद संविदा कर्मी बदहाल

गोरखपुर गोरखपुर/बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर के एक तरफ कंपनी धमकी दे रही है कि सिस्टम बंद होने के बाद संविदा कर्मी के उपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

जहाँ एक तरफ लेखपाल व पुलिस कर्मी सबस्टेशन चला रहे हैं संविदा कर्मी किस के हिसाब से काम करें सभी कर्मियों के दिलों में दहशत बना हुआ है एक तरफ कंपनी अगर लाइट बाधित होती है तो संविदा कर्मियों को ऊपर एफआईआर करने के मूड में है जिसके कारण विद्युत संविदा कर्मी डरे और दिलो में दहशत बना हुआ है जहा पर एक तरफ विद्युत विभाग दूसरी तरफ बेसिल कंपनी दोनों अपने अपने नियम बता कर संविदा कर्मियों को अपना अपना नियम बता रहे हैं किसके कहने पर कार्य किया जाए अगर विभाग की बात मानी जाये तो बेसिल कम्पनी संविदा कर्मी के उपर एफआईआर दर्ज कराये कि अगर बेसिल कंपनी की बात मानी जाए तो विभाग बाहर का रास्ता दिखाएगा इन सभी बातों को रखते हुए संविदा कर्मियों में दहशत का माहौल है अगर काम किया जाए तो किसके बदौलत किया जाए जहा तक यह देखा जा रहा है कि सबस्टेशन पर लेखपाल और पुलिस कर्मी के भरोसे छोड़ दिया गया है मौके पर सरहरी फिडर पर जाने पर पता चला की लेखपाल गायब है। सिर्फ सरहरी पुलिस चौकी के दो सिपाही राहुल कुमार व चन्दन चौरसिया व एसएचओ शिव कुमार ही मौजूद हैं। थोडी देर के लिये अवर अभियंता जूनियर अवधेश कुमार आये और सेल्फी लिये और चल दिये। कैसे चलेगी बिजली सप्लाई पानी और अन्धेरे में रहने को ग्रमीण मजबूर अगर यही स्थिति रही तो आने वाला दिन और ही उग्र होगा!

योगी सरकार ने 3 माह के लिये टाला निजीकरण बिजली कर्मियों ने वापस ली हड़ताल

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी हाथ में सौंपने का फैसला फिलहाल तीन माह के लिये टाल दिया है

गोरखपुर लखनऊ=/उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी हाथ में सौंपने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। सरकार द्वारा निजीकरण को टालने को लेकर लिये गये इस बड़े फैसले के बाद बिजली कर्मचारियों ने भी अपना कार्य बहिष्कार वापस ले लिया है। अवधनगरी को मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने बिजली विभाग के निजिकरण को फिलहाल 15 जनवरी 2021 तक के लिये टाल दिया है। इससे पहले सीएम योगी से मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ भी हाइलेवल बैठक भी की थी।

उत्तर प्रदेश सरकार और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच चली लंबी बैठक के बाज बिजली व्यवस्था के निजीकरण का फैसला टालने पर बिजली कर्मचारियों ने खुशी जतायी है। इस फैसले के बाद बिजलीकर्मियों की अनिश्चिकालीन हड़ताल को कर्मचारी संगठनों ने वापस ले लिया है। इससे पहले यूपी की योगी सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी हाथ में सौंपने के फैसले के खिलाफ बिजलीकर्मियों सोमवार को अनिश्चिकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। आज मंगलवार को हड़ताल के दूसरे दिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी थी, जिससे यूपी में संकट गहराने के आसार बढ गये थे। योगी सरकार भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल टालने के प्रयासों में जुटी हुई दिखी। जनता के बढ़ते आक्रोश से भी सरकार पर लगातार दबाव नजर आ रहा था। कई दौर की मीटिंग के बाद आखिरकार सरकार ने निजीकरण के फैसले को तीन माह तक टालने का निर्णय लिया।

कृषि विधेयक से होगा किसानों का सर्वोत्थानः वेद प्रकाश गुप्ता

कृषि विधेयक 2020 के संदर्भ में विधायक ने अयोध्या विधानसभा में चौपाल किया आयोजित इस दौरान सभी किसानो को बताया गया विधेयक की विशेष महत्ता व उपयोगिता

अयोध्या। पूरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत हैबतपुर में मंगलवार को अपराह्न कृषि विधेयक 2020 के संदर्भ में चौपाल आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता रहे। श्री गुप्ता ने किसानों को कृषि विधेयक की विशेष महत्ता बताए। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक से यमयसपी कभी प्रभावित नही होगा। इससे किसानों को और बेहतर मूल्य मिलेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में किसानों के लिए यमयसपी का कुल भुगतान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने में जुटा है, उनके पास कोई मुद्दा नही है। किसानो की सच्ची हितैषी भाजपा व योगी मोदी की सरकार ही है। इस विधेयक से अब किसानों का सम्पूर्ण उत्थान व विकास होगा। यह विधेयक सदैव किसान हितकारी है। इससे पूर्व श्री गुप्ता का संजय गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ताओ ने फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ट भाजपा नेता हरिभजन गौड़ ने किया। जबकि संयोजक लक्ष्मण वर्मा रहे। कार्यक्रम में बाल कृष्ण वैश्य, संजय गुप्ता, राम जनम वर्मा, घनश्याम अग्रहरि, अरविंद वर्मा, अशोक वर्मा, मेवालाल, देवेंद्र दूबे, हरि बक्श कोरी, सुनील वर्मा, सतीश चंद्र व राम बरन वर्मा आदि शामिल रहे।

समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज शब्बीर कुरैशी के परिवार वालों से की मुलाकात

गोरखपुर/ समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में शब्बीर कुरैशी के घर जाकर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए परिवार को आश्वस्त किया और यह वादा किया समाजवादी पार्टी उनके सुख दुख में खड़ी है और रहेगी भाजपा सरकार ने शब्बीर कुरैशी को जेल भेजकर व उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सील करके उनका उत्पीड़न कर रहीं हैं प्रतिनिधिमंडल ने उनके परिजनों से कहा कि समाजवादी पार्टी उनके व उनके परिवार के साथ खड़ी है पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी लडेगी जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा कि भाजपा सरकार जनहित के लिए कार्य करने वाले विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाकर जेल भेज रहीं हैं पूलिसिया उत्पीड़न के शिकार पार्टी नेता के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है और पार्टी उनकी पूरी लडाई लडेगी इस दौरान प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, जियाउल इस्लाम ,अखिलेश यादव, विजय बहादुर यादव, अवधेश यादव, रजनीश यादव, सिंहासन यादव, शहाब अंसारी, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, बिंदा देवी, एहतेशाम खान ,राहुल यादव, कपिल मुनि यादव, करुना निधान प्रमोद यादव बिजेन्द्र अग्रहरि चर्चिल अधिकारी आजम लारी शहादत अली सिद्दिकी आदि मौजूद रहे।

संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव हत्या की आशंका

अवध नगरी संवाददाता गोरखपुर/उरुवा थाना क्षेत्र के माल्हनपार रोड पर मरचा गांव के पास स्थित पुलिया के पास पानी में तैरते एक युवक का शव मिला है। उरूवा पुलिस ने शव को निकलवा कर उसके शिनाख्त का प्रयास कर रही है अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह पुलिया की ओर गए लोगों ने शव को देखा और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पुलिस गुमशुदगी रजिस्टर को भी तलाश रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शव पर चोट के निशान दिख रहे हैं। जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी।

विधायक ने किया पक्की सड़कों का शिलान्यास

गोरखपुर/पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड चरगावां अंतर्गत ग्रामसभा सरैया तुलसी देवी अन्य जिला मार्ग का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य एवं विकासखंड भटहट अंतर्गत बिस्मिल्लह नहर से बरौली नहर होते हुए बेलवा रायपुर तक संपर्क मार्ग की। एवं ग्रामसभा हाफिज नगर से बूढ़ाडीह इटहिया होते हुए बड़ी रतवा हिया तक मार्ग का नव निर्माण कार्य की आधारशिला वैदिक मंत्रोचार के बीच पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महेंद्र पाल सिंह ने रखीं एवं सभा को संबोधित करते हुए ग्रामीणों से कहा कि आपके गांव सभा में आवागमन के निमित्त हो रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के असीम स्नेह के उपरांत शासन की त्वरित विकास योजना निधि से लोक निर्माण विभाग के द्वारा। 01-ग्रामसभा सरैया तुलसी देवी अन्य जिला मार्ग का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण सड़क निर्माण कार्य दूरी 8.300 किमी लागत 90.44 लाख रुपए।

स्वास्थ्य उप केंद्रों पर मिल रही सुविधाओं को दीवार पर लिखवाने का दिया निर्देशः जिलाधिकारी

पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुई समीक्षा बैठक

बस्ती। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बोर्ड लगाने तथा यहां दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को दीवार पर लिखवाने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि यहां उपकेंद्र खुलने एवं बंद होने का समय भी लिखवायें। उन्होंने कहा कि उपकेंद्र प्रतिदिन खुले तथा लोगों को आवश्यक सुविधाएं भी दी जायें।

उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि पहली अक्टूबर को निरीक्षण में 273 में से 204 केंद्र खुले मिले। वास्तव में अधिकारियों ने इन उपकेंद्रों का निरीक्षण किया। एएनएम उपस्थित मिलीं। कहीं-कहीं उनके साथ आशा भी थी। उपकेंद्र पर साफ-सफाई रही। 122 उपकेंद्र पर अनटाइड फंड का पैसा भी उपलब्ध था।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनटाइड फंड की धनराशि दस हजार रुपये से उपकेंद्र का रंग-रोगन, साफ-सफाई के लिए आवश्यक सामान, उपकरण, फर्नीचर की मरम्मत कराया जाये। उल्लेखनीय है कि जिले के तीन स्वास्थ्य केंद्र प्रदेश में 100 केंद्रों की सूची में शामिल है। कुल 273 उपकेंद्रों में 108 आरोग्य केंद्र के रूप में चिन्हित है।

उन्होंने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य उपकेंद्रो का विभागीय अधिकारी नियमित निरीक्षण करें तथा यहां की समस्याओं का निस्तारण करें। प्रत्येक सोमवार को इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी एमओआईसी को भी निर्देश दिया कि उपकेंद्र पर तैनात एएनएम को अनावश्यक बैठक में ना बुलायें। जब ज्यादा जरूरी हो तो सुनिश्चित करें, एएनएम के ना रहने पर कोई आशा या संगिनी अवश्य केंद्र पर मौजूद रहे।

उन्होंने निर्देश दिया कि 51 उपकेंद्रों पर जहां प्रसव कराने की सुविधा उपलब्ध हो, उसे और अधिक सुसज्जित किया जाए ताकि लोगों का विश्वास इन सेवाओं के प्रति जगे। स्वास्थ्य उपकेंद्रों की सक्रियता से विभाग की तमाम योजनाओं को गति मिलेगी।

स्वास्थ्य उपकेंद्रों की रिपोर्ट राजेश पाण्डेय ने प्रस्तुत किया। बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, सीएमओ डॉ0 एके गुप्ता, एसडीएम आसाराम वर्मा, नन्द किशोर कलाल, आनंद श्रीनेत, नीरज पटेल, डॉ0 सीके वर्मा, डॉ0 फखरेयार हुसैन, डॉ0 जलज, आलोक राय, डॉ0 बृजभूषण मौर्य, जगदीश शुक्ला एवं सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे।

विशेष संचारी रोग अभियान के तहत समीक्षा बैठक में डीएम ने दिया अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश

बस्ती। विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह के अंतर्गत चिन्हित 115 में से मात्र 53 गंभीर सांस रोगियों का कोरोना टेस्ट कराने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने असंतोष व्यक्त किया है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने 24 घंटे के भीतर सभी सांस रोगियों की जांच कराने के लिए एमओआईसी को निर्देश दिया है। संचारी रोग अभियान के 04 दिन के भीतर 161 बुखार, 98 खांसी तथा 17 सांस रोगी चिन्हित किए गए हैं। इसमें से केवल 53 रोगियों का कोविड टेस्ट हुआ है। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे अक्टूबर माह में संचालित इस अभियान में आशा घर-घर जाकर टीकाकरण से वंचित बच्चों को चिन्हित करें। ऐसे सभी बच्चों को नवम्बर माह में अभियान चलाकर टीकाकरण कराया जाएगा। घर- घर जाने और लोगों को जागरूक करने के दौरान वे कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करेंरू मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं तथा इसके लिए लोगों को जागरूक करें। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि आशा के सभी प्रकार के मानदेय का समय से भुगतान सुनिश्चित कराएं। इस संबंध में उन्होंने सभी एमओआईसी को निर्देश दिया कि बिल वाउचर तैयार कर मुख्यालय भिजवायें। वित्त एवं लेखाधिकारी इसका परीक्षण कर भुगतान सुनिश्चित करायें। विशेष संचारी रोग अभियान की समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि 1235 ग्राम पंचायतों में से 271 ग्राम में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति तथा मातृ समिति की बैठक हो चुकी है। 42 इंडिया मार्क टू हैंडपम्प ठीक कराए गए हैं। 310 शैलो हैंडपम्प पर लाल निशान लगाया गया है। 22 वार्ड में फागिंग कराई गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एमओआईसी अतिकुपोषित बच्चो को एनआरसी भिजवायें। यदि कोई छोटा बच्चा है तो वह भी मां के साथ एनआरसी में रह सकेगा। समीक्षा के दौरान उन्हें बताया गया कि आकाशदीप संस्था द्वारा अभिभावकों से पैसा लेकर बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है जबकि टीका लगाने की निशुल्क सुविधा अस्पतालों में है। जिलाधिकारी ने ऐसी संस्था के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, सीएमओ डॉ0 एके गुप्ता, एसडीएम आसाराम वर्मा, नंदकिशोर कलाल, आनंद श्रीनेत, नीरज पटेल, डॉ0 सीके वर्मा, डॉ0 फखरेयार हुसैन, डॉ0 जलज, आलोक राय, डॉ0 बृजभूषण मौर्य, जगदीश शुक्ला एवं सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे।

पंखे से लटकता मिला एंबुलेंस ड्राइवर का शव, इलाके में फैली शोक की लहर

दुबौलिया। थाना क्षेत्र के अतंर्गत एक युवक के फांसी लगाने का मामला सामने आ रहा है, दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में 32 साल के एक युवक ने पंखे से लटकर फांसी लगा ली, जिसके कुछ समय बाद परिजनों को भनक लगते ही आनन-फानन में उचे पंखे से नीचे उतार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुत्ताबिक घटना से परिजनों में मातम छाया हुआ है, वहीं परेशान पीड़ित परिजनों द्वारा घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, और साथ ही शव को कब्जें में कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। इस मामले पर बताया जा रहा है कि ये मामला दुबौलिया के थाना क्षेत्र संसारपुर का है, जहां गांव निवासी विपिन पुत्र राम किशोर बलरामपुर में एंबुलेंस के पद पर तैनात था, परिजनों का कहना है कि काम पर से घर आकर खाना खाकर चुप-चाप अपने कमरे में चला गया।

गोरखपुर की 46 ग्राम पंचायतों को अपनी सीमा में शामिल करने को तैयार नहीं है नगर निगम

गोरखपुर/जिले की 46 ग्राम पंचायतें पिछले 5 दिन से अपना वजूद तलाश रही हैं। इन ग्राम पंचायतोंको शहरी क्षेत्र में शामिल किए जाने की घोषणा के बाद पंचायती राज विभाग ने 1 अक्टूबर से इन्हें अलग कर दिया है। 30 सितंबर को खाते पर रोक लगाने के साथ ही गांव में तैनात सचिव व सफाई कर्मी भी हटा लिए गए हैं। नियमानुसार पंचायतों को नगर निगम व नगर पंचायतों में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन नगर निगम के अधिकारी बिना लिखित आदेश के शामिल करने को तैयार नहीं है। कुछ नगर पंचायते, गांवों को शामिल करने की बात कह रही है, लेकिन वहां भी चार्ज नहीं लिया गया है। इन ग्राम पंचायतों को नगर निगम व नगर पंचायतों में शामिल करने के लिए अधिसूचना पूर्व में जारी हो चुकी है। पहले 30 जून तक इन्हें पंचायती राज विभाग से अलग होना था, लेकिन खातों में पड़े धन के उपयोग के लिए समय सीमा 3 महीने बड़ा दी गई थी। पांच दिन से इन पंचायतों में सफाई कार्य भी ठप है। कुछ पंचायतों में जलभराव भी है।इससे निजात के लिए सोमवार को नगर निगम के अनुरोध पर पंचायती राज विभाग ने वाटर पंप लगाया है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि साफ-सफाई का जिम्मा नगर निगम का है। जबकि नगर निगम की अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में उन्हें शासन से दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ग्राम पंचायतों के खातों पर रोक लगाकर 30 सितंबर को ही जानकारी शासन को दे दी गई है। सफाई कर्मी व सचिव भी हटा लिए गए हैं। तीन गांवों में परफामेंस ग्राट का पैसा है, उसको लेकर अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। खोराबार ब्लॉक में सेदुली बेदुली, भरवलिया बुजुर्ग, बड़गो,झरवा,सेमरा देवी प्रसाद, गायघाट बुजुर्ग, जंगल सिकरी, सिक्टौर,कजाकपुर, रामपुर क, खोराबार उर्फ सूबाबाजार, चरगावा ब्लॉक में नुरूद्दीनचक, मुडिला उर्फ मुंडेरा, हरसेवकपुर नंबर दो, गुलरिहा,करमहा, जंगल हकीम नम्बर दो, जंगल तिनकोनिया नम्बर एक, जंगल बहादुर अली, भटहट ब्लॉक में सोनराइच,मुडेरी गड़वा, सिधावल,हरखापुर,पिपरा मुगलान,खझवा,भरोहिया ब्लॉक मे तिघरा, जंगल बिहुली, जंगल झझवा, जंगल अगही, साहबगंज, बगहीभारी, हरपुर, कोल्हुआ, कैंपियरगंज ब्लॉक में बनभागलपुर, कैंपियरनगर, बसंतपुर, चौमुखा, जनकपुर,सरदारनगर ब्लॉक में चौरा, भगवानपुर,बाल बुजुर्ग,बाल खुर्द,भोपा बाजार, राघोपुर।

फसल की कीमतों का भी आश्वासन मिले

अप्रैल से जून की तिमाही में जीडीपी के 24 प्रतिशत तक गिरने के बीच कृषि क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि एक उम्मीद की किरण रही. भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, जब कृषि के सूखा या मानसून संकट के कारण प्रभावित नहीं होने के बावजूद हम गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. एक सकारात्मक बात रही कि रबी फसलों, खास कर गेहूं की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद हुई है. पंजाब और हरियाणा जैसे बड़े उत्पादक राज्यों के साथ-साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी केंद्र सरकार के भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) ने रबी की अच्छी खरीद की. जब एफसीआइ नामित एजेंसियों के माध्यम से खरीद करती है, तो इसका मतलब होता है कि किसानों को सुनिश्चित लाभ यानी निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिला है, जो कि इस समय 19,00 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक रहा.एमएसपी का निर्धारण राजनीतिक फैसला है, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के इनपुट पर आधारित होता है. इस आयोग का गठन 60 वर्ष पहले हुआ था और यह लागत के आधार पर फसलों के लिए कितना उचित मूल्य तय हो, उसे तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से तय करता है. बीज, कीटनाशकों, डीजल, कर्ज, उर्वरकों आदि से कृषि लागत बढ़ने के कारण एमएसपी का भी बढ़ाया जाना जरूरी है, ताकि किसानों को पर्याप्त लाभ मिल सके. अन्यथा यह घाटे का सौदा है. बीते 50 वर्षों में गेहूं और चावल के लिए एमएसपी औसतन छह प्रतिशत की दर से बढ़ी, लेकिन इस अवधि में सरकार द्वारा खरीद 70 से 80 गुना तक बढ़ गयी. एफसीआइ द्वारा खरीद तीन उद्देश्यों से की जाती है- पहला किसानों को पर्याप्त समर्थन मूल्य मिले, दूसरा कि बफर भंडारण कर राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो और तीसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए अनाज उपलब्ध हो सके, ताकि राशन दुकानें इसे गरीबों और जरूरतमंदों को दे सकें. किसानों को भुगतान किये जानेवाले और पीडीएस से प्राप्त मूल्य के बीच का अंतर केंद्र सरकार के बजट की खाद्य सब्सिडी है. यह दो लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है, यानी जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर. खरीद प्रक्रिया व्यापक है. यह गेंहू और धान को मिला कर 90 मिलियन टन से अधिक हो चुकी है. एमएसपी के अंतर्गत 23 फसलों को शामिल किया जाता है. इसमें अनाज, तिलहन, दालों के अलावा गन्ना व कपास जैसी वाणिज्यिक फसलें भी होती हैं, लेकिन वास्तव में अधिकांश खर्च केवल दो फसलों- गेंहू और धान पर ही किया जाता है. राष्ट्रीय नीति होने के बावजूद, एफसीआइ को फसल बेचनेवाले किसान मात्र आधा दर्जन राज्यों से ही होते हैं. यह देश में कुल किसानों का मात्र छह प्रतिशत ही हिस्सा है. एफसीआइ द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद होती है, जो देश में कुल अनाज उत्पादन की लगभग एक तिहाई है. कृषि अर्थव्यवस्था में यह बड़ी पहल है और इससे विश्व व्यापार संगठन नाखुश रहता है. साल 1994 में डब्ल्यूटीओ का गठन कर रहे लोगों को भारत यह बताने मे सफल रहा था कि कुल मिलाकर भारतीय किसानों को इससे संरक्षण नहीं मिल रहा है, सरकार की तरफ से यह नकारात्मक समर्थन है. वास्तव में, व्यापार की शर्तें उद्योगों के मुकाबले किसानों के खिलाफ हैं और इसकी भरपाई एमएसपी जैसे उपायों से करने की कोशिश की जाती है. हालांकि, अगर एफसीआइ खरीद से केवल छह प्रतिशत किसानों को ही लाभ मिलता है, तो भी तय एमएसपी का फायदा अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर किसानों को मिल रहा है. संभवतः पहली बार, 40 साल पहले करिश्माई नेता शरद जोशी के नेतृत्व में किसानों का व्यापक आंदोलन हुआ था. वे गणित स्नातक थे और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि नहीं थी. फिर भी, वे किसानों को समझते थे, उनका नारा था- हमारी मेहनत और पसीने की सही कीमत दो. यह 1978-79 का प्याज किसानों का प्रसिद्ध आंदोलन था, 1981 में तंबाकू किसानों का भी आंदोलन हुआ. प्रकृति की मार झेलनेवाले किसान, ऊपर से बिचौलियों के शोषण की वजह से और भी बुरे हालात में पहुंच जाते हैं. वे छल और कपट से छोटे किसानों का बहुत शोषण करते हैं. इसी वजह से कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) का प्रस्ताव आया, और इस व्यवस्था को 1960 में पूरे देश में लागू किया गया. यह माना गया कि नियमित चुनाव और किसानों की भागीदारी से इसे लोकतांत्रिक तरीके से संचालित किया जायेगा. सदियों से मौजूद मंडी व्यवस्था का यह औपचारीकरण था, लेकिन बाद के वर्षों में राजनीतिक और वंशवाद के निहित स्वार्थों के लिए एपीएमसी प्रणाली पर कब्जा कर लिया गया. वर्तमान में मात्र 4000 ही एपीएमसी बाजार केंद्र हैं, जबकि पूरे देश में 40,000 बाजार केंद्रों की आवश्यकता है. एपीएमसी सिस्टम के लाइसेंसराज की किसानों और खरीदारों पर मजबूत पकड़ होती है, जिससे उन्हें इस वैधानिक बिचौलिये के आगे मजबूर होना पड़ता है. नया कृषि कानून इस बिचौलिये की ताकत को कम करेगा. अब किसान अपनी उपज को एपीएमसी या उससे बाहर भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन इस सुधार का परिणाम आने में अभी वक्त लगेगा. कॉरपोरेट हितों को साधनेवाले एक नये प्रकार के बिचौलियों के उभरने का डर है, लेकिन अनजान डर की वजह से सुधारों को टाला तो नहीं जा सकता. हालांकि, कीमतों को लेकर कुछ आश्वासन योजना की जरूरत है, जोकि एफसीआइ और एमएसपी माध्यम से तय होती हैं. पूर्ण विकसित बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, किसानों के लिए वायदा बाजारों से मूल्य आश्वासन की व्यवस्था है, लेकिन इसे अटकलबाजी माना जाता है. वायदा बाजार को अधिक तरल और कीमत निर्धारण को पारदर्शी बनाने की जरूरत है. तब तक के लिए एमएसपी के रूप में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है. इस बात का भय है कि एपीएमसी को कमजोर किये जाने से एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जायेगी, जिससे किसान आक्रोशित हैं. इसका समाधान केवल मौखिक आश्वासन ही नहीं, बल्कि नीति निर्माताओं को लिखित रूप में भी देना चाहिए. इस जरूरी सुधार से यह कृषि कानून, कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधार का महत्वपूर्ण कदम होगा।

सम्पादकीय

चोटी की कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में भारी वृद्धि

यद्यपि जुलाई-अगस्त महीने की तुलना में सितंबर माह में अनेक क्षेत्रों में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के कारण भारत की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई पड़ा है किंतु पिछले साल 2019 के सितंबर माह के स्तर पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में काफी समय लग सकता है। दूसरी ओर भारत के शेयर बाजार में कारपोरेट सेक्टर के दिशा और दशा के बैरोमीटर कहे जाने वाले बंबई शेयर बाजार के सेंसैक्स तथा राष्ट्रीय शेयर बाजार के निफ्टी दोनों मजबूती से अपने-अपने वर्ग में जमे हुए हैं। सितंबर माह में दो दिन हुई मुनाफा बिकवाली के दिनों को छोड़कर सेंसैक्स 37,000 से 39,000 की रेंज में तेजी से उछाल लेता तथा गिरता रहा। सेंसैक्स में 500 बिन्दु की तेजी या गिरावट दोनों ही समाचारों की सुर्खियां बनते रहे। निफ्टी 11,300 से 11,500 के बीच चढ़ता गिरता रहा। 1 अक्टूबर को सेंसैक्स 38,697 तथा निफ्टी 11,416 पर बंद हुए। 1 अक्टूबर को बीएसई में सूचीकृत 30 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 156 लाख करोड़ रुपए का हुआ ।1 अक्टूबर को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियां ये थींरू रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचएडएफसी बैंक, हिन्दुस्तान यूनीलीवर, इंफोसिस, एचएडएफसी हाउसिंग, कोटक महिन्द्रा, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एअरटेल और एचसीएल टेक। पिछले दो दशक से बाजार पूंजीकरण रिलायंस इंडस्ट्रीज चोटी पर जमी हुई है। आज इसका बाजार पूंजीकरण 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक है जबकि बाजार पूंजीकरण में दूसरे स्थान पर स्थान बनाए रखने वाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूंजीकरण 60 प्रतिशत से अधिक है। पिछले सप्ताह देश विदेश के वित्तीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में रिलायंस इंडस्ट्रीज सुर्खियों में छाई रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा कारोबार की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स में अमेरिका की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी निवेशक सिल्वर लेक ने 1.32 प्रतिशत इक्विटी के लिए साढ़े सात हजार करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। रिलांयस ने एक पखवाड़ा पहले खुदरा कारोबारी कंपनी फ्यूचर ग्रुप का 24713 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 9 लाख 46 हजार करोड़ रुपये है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा टाटा ग्रुप की कंपनियों में एक बड़ा अन्तर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैनर तले मुकेश अंबानी के सभी बड़ी कंपनियां हैं जबकि टाटा ग्रुप में टीसीएस, टाटा स्टील एवं टाटा मोटर्स सेंसैक्स में शामिल हैं जबकि टायटन, टाटा टी, इंडियन होटल्स आदि बड़ी कंपनियां में शेयर बाजार में सूचीकृत है । इन कंपनियों का प्रबंधन भी अलग है। टीसीएस के शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य 2522 रुपये है। बाजार पूंजीकरण में तीसरे स्थान पर एचएडएफसी बैंक जिसका बाजार पूंजीकरण 6 लाख करोड़ रुपये है। इसके शेयर की वर्तमान कीमत 1106 रुपये है। बाजार पूंजीकरण में चोटी की पांच कंपनियों में हिन्दुस्तान यूनीलीवर 5 लाख करोड़ रुपये और इंफोसिस 4 लाख करोड़ के साथ क्रमशरू चौथे और पांचवें स्थान पर है। सितंबर माह में फाइनैंसियल, बैंकिंग, ऑटो और आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। बीएसई बैंक्स में दो प्रतिशत, आईटी इंडेक्स में 3 प्रतिशत टेक इंडेक्स में 2 प्रतिशत की तेजी रही। सितंबर माह में लगभग 3000 कंपनियों के शेयरों में सौदे हुए। इनमें से 55 प्रतिशत कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही। इस कोरोना लॉकडाउन काल में भी 122 कंपनियों के शेयर एक साल के उच्च स्तर पर रहे जबकि मात्र 62 कंपनियों के शेयर एक साल के निम्न स्तर रहे। सितंबर माह में बाजार में तेजी का एक प्रमुख कारण विदेशी पोर्टफोलिया निवेशकों द्वारा भारतीय शेयरों की जमकर लिवाली की जाना भी रही है। अमेरिका में राहत पैकेज आने की संभावानाओं के कारण भी दुनिया के सभी शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। अक्टूबर माह से त्योहारों का मौसम प्रारंभ हो रहा है जिसमें आमतौर पर ऑटो सहित कंज्यूमर ड्यूरेबल की उपभोक्ताओं द्वारा अच्छी मांग रहती है। कोरोना लॉकडाउनकाल में भी सितंबर माह में ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े उनकी अपेक्षाओं से बेहतर रहे। सितंबर माह में दुनिया के सभी शेयर बाजारों में तेजी रही। अमेरिकी शेयर बाजार के इंडेक्स डाउ जोस, नेस्डेक, एस एंड पी 500, जापान का निक्केई, चीन का सीएसआई, आस्ट्रेलिया का एसीएक्स-20 सभी उच्च स्तर रहे । पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पोजीटिव होने के समाचार ने अमेरिकी शेयर बाजार में नरमी के रुख के कारण डाउ जोंस में 0.48 प्रतिशत, नेस्डेक कंपोजिट में 2.22 प्रतिशत और एस.एंड पी 500 इंडेक्स में 0.96 प्रतिशत की गिरावट रही थी। इस कारण गुरुवार को भारत सहित दुनिया के अन्य शेयर बाजारों में भी हल्की नरमी देखी गई थी।

बिहार की चुनावी राजनीति और लोकजनशक्ति पार्टी

बिहार चुनाव में राजग की सहयोगी रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी ने बिहार में एकला चलो की रणनीति अपना ली है। बिहार में राजग के साथ उसके गठबंधन की गांठ खुल जरूर गई है लेकिन टूटी नहीं है। उसका विरोध सिर्फ नीतीश कुमार की जनतादल यूनाईटेड तक सीमित है। लोकजनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को नीतीश पर छोड़ दिया है और वह नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव में उतर रही है कि राजग के वे ही मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जदयू से एक सीट कम पर चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से भाजपा 121 पर तो जदयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन पर मुहर लगा दी है। लोजपा का बिहार में नारा है मोदी जी से वैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं।

लोजपा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ रही है और बिहार में अपनी अलग ढपली अलग राग अलापने का निर्णय लिया है। लेकिन, वह केन्द्र की सरकार में वह बनी रहेगी। भाजपानीत केन्द्र के राजग गठबंधन से उसका नाता नहीं टूटा है। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता रहा है कि वे मौसम का हाल बहुत अच्छी तरह से समझते आये हैं वे इतने अच्छे ढंग से मौसम का पूर्वानुमान कर लेते हैं कि केन्द्र की सरकार चाहे जिसकी हो उसमें वह मंत्री जरूर बन जाते हैं। फिलहाल वे केन्द्र सरकार में मंत्री हैं और उनके बेटे ने भी उनसे यह सीख ले ली है। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में राजग गठबंधन के सीटों की घोषणा होने के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसमें नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाईटेड 122 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के अन्य दलों को ये पार्टियां ही अपने कोटे की सीटों से समायोजित करेंगीं।बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी श्हमश् (हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा)का समायोजन जदयू ने किया है उन्हें छह सीटें दी गई है, जहां से वे स्वयं व उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यदि लोजपा अपने स्थान पर अडिग रहती है तो बिहार के चुनाव में राजग के ही दो चेहरे मैदान में होंगे एक भाजपा द्वारा घोषित नीतीश कुमार और दूसरे लोजपा के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। इससे यही लगता है कि यह सब कुछ अनायास नहीं, भाजपा और लोजपा की आन्तरिक समझ का परिणाम है कि लोजपा जदयू के खिलाफ चुनाव लड़े और केन्द्र में गठबंधन का हिस्सा भी बनी रहे क्योंकि इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला है उल्टे उसे लोजपा का समर्थन भी हासिल होगा जो जनतादल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को नहीं रहेगा। लोजपा के इस निर्णय के अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं जिसे नीतीश कुमार भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे। नीतीश कुमार भी राजनीति के अच्छे खिलाड़ी है अपने इसी खेल से उन्होंने चुनाव राजद के साथ लड़ा था और फिर सरकार भाजपा के साथ बनाई। जो नीतीश कुमार नरेन्द्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते थे अब वे एक दूसरे की राजनीतिक पसन्द और मजबूरी बन चुके हैं। भाजपा के अन्दर बिहार में नीतीश के खिलाफ आवाज उठती रही है। बिहार भाजपा अपने बूते पर चुनाव लड़ने की इच्छुक रही है जिससे सिर्फ उसी का शासन हो। उसे वैसाखी की जरूरत तभी तक है जब तक वह अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती है।

पिछले तीन चुनाव में उसकी स्थिति ऐसी नहीं रही है कि वे अकेले के बलबूते पर सरकार बना सके। राजद का गठबंधन तोड़कर नीतीश को अपने साथ लाने का प्रयत्न उसका सार्थक रहा। लोपजा अब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हाथों में है, लोजपा 40 से अधिक सीटें चाह रही थी जो नीतीश को गंवारा नहीं हुआ। इसलिए उसने अलग 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उसकी यह घोषणा बिहार की 243 सीटों में सिर्फ 143 सीटों के लिए है यानी जो सीटें उसे दी जा रही थीं और वे 122 सीटें वे होंगी जिनपर जदयू चुनाव लड़ेगी। भाजपा की चाहत है कि वह नीतीश से बाजी मारकर आगे हो जाये। लोजपा की रणनीति का एक हिस्सा यह भी है। क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि नीतीश से बाजी मार लेगी। वह नीतीश को नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश करेगी। गठबंधन की राजनीति का यह रस्साकशी चुनाव परिणाम आने पर ही पता चल सकेगा कि किसने किसको शह और किसने किसको मात दी। नीतीश के गठबंधन सामने लालू की पार्टी तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल है जिसके गठबंधन के साथियों में कांग्रेस, वामपंथी दल शामिल हैं। तेजस्वी के गठबंधन में शामिल होने वाली वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी गठबंधन के लिए दलों की सूची घोषित करने के साथ ही विदक गये क्योंकि वे 25 सीटें और उपमुख्यमंत्री पद की चाहत रखते थे जब तेजस्वी ने उन्हें अपनी सीटों में से बिना किसी नम्बर के जेएमएम और वीआईपी पार्टी को समायोजित करने की घोषणा की तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन्होंने राजद गठबंधन से अलग प्रेस कांफ्रेंस करके अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। जहां तक राजग गठबंधन के सामने राजद के गठबंधन का मामला है वह भी अपने ही अन्तर्विरोधों से घिरी है। घर से लेकर पार्टी तक इसके दर्शन होते रहे हैं।

लालू यादव काल के नेतागणों मे तेजस्वी के कार्यकलापों को लेकर उनसे दूरी बना ली है जो है भी वे मूकदर्शक हो गये हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने जीवन के अंत समय में राजद से नाता तोड़ लिया। ऐसे में राजद के सामने राजग जैसे मजबूत गठबंधन जो सत्ता में है उससे मुकाबला बहुत आसान नहीं दिख रहा है। कोरोना काल और लॉकडाउन में जिस प्रकार बिहार में हालात रहे उसे सभी ने वह चाहे बिहार के अन्दर रहे हों या बिहार के बाहर सरकार को देखा, परखा और समझा है। कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक हिंसा या प्रवासी मजदूरों और स्वास्थ्य सेवाओं का, सुशासन बाबू का बाजा बज गया है। ऐसे में बिहार जिसे राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक माना जाता रहा है वह चुनाव में किस राजनीतिक करवट बैठेगा आने वाला समय बतायेगा।

नये कृषि कानूनों में सुधार की दरकार

केंद्र सरकार 5 जून, 2020 को कृषि से संबंधित तीन अध्यादेश लेकर आयी. इन तीनों अध्यादेशों को संसद के मानसून सत्र में विधेयकों के रूप में प्रस्तुत कर, लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदित कर दिया गया. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक अब कानून बन गये हैं. इनमें पहला अधिनियम है, 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020'. इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर कृषि व्यापार को उदार एवं सुगम बनाना है. बहुत पहले से अधिकांश कृषि जिंसों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता रहा है, ताकि लोग उसका अनुचित भंडारण न कर सकें और कीमतों में वृद्धि को रोका जा सके. यह तब के लिए ठीक था, जब देश में कृषि खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज आदि का अभाव था. व्यापारी इस अभाव का लाभ उठाते हुए खाद्य पदार्थों को बाजार में आने से रोककर कीमतें बढ़ा देते थे. यह कानून कृषि विकास के लिए बाधक बन रहा था. आज जब कृषि उत्पादन सरप्लस में है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव कर अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेलों, आलू, प्याज इत्यादि को आवश्यक वस्तु से बाहर करने का सोचा गया, ताकि इन वस्तुओं का बड़ी मात्रा में निजी क्षेत्र द्वारा भंडारण किया जा सके. दूसरा अधिनियम है 'किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020'. इस अधिनियम के तहत, अब कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त कृषि मंडी से बाहर भी हो सकेगी. अभी तक के प्रावधानों के अनुसार, किसान अपनी फसल को सरकार द्वारा नियंत्रित कृषि उत्पाद मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) मंडी में लाता था, जहां आढ़तियों और व्यापारियों के माध्यम से उसे बेचा जाता था. सरकार या निजी व्यापारी मंडी से ही कृषि वस्तुओं की खरीद करते थे. सरकार का तर्क है कि नयी व्यवस्था में किसानों को मध्यस्थों से छुटकार मिलेगा और खुले बाजार में बेचते हुए उन्हें मंडी शुल्क और मध्यस्थों को कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा. इससे किसान को उपज के बदले ज्यादा पैसा मिलेगा. हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद पूर्व की भांति एपीएमसी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. तीसरा अधिनियम है 'किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम, 2020'. इस अधिनियम में कृषि उत्पाद के लिए निजी कंपनियों अथवा व्यक्तियों द्वारा किसानों के साथ संविदा खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) की व्यवस्था की गयी है. यह एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन विवाद की स्थिति में किसानों को सही समाधान मिलने में व्यवस्थागत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि प्रस्तावित विवाद समाधान तंत्र किसानों के लिए बहुत जटिल है. विवाद निबटान में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की भूमिका महत्वपूर्ण बतायी गयी है. यह सही व्यवस्था नहीं है, क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह कंपनियों के शोषण का शिकार हो सकता है।

इसके लिए किसान न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अधिकांश किसान एक से दो एकड़ भूमि पर ही खेती करते हैं और हमारी जोत का औसत आकार एक एकड़ से भी कम है. ऐसे में किसान का कंपनियों की ताकत के सामने खड़ा रह पाना संभव नहीं. यह एक गैर-बराबरी की व्यवस्था है, जिसमें सुधार करना होगा. जहां कई राजनीतिक दल और किसान संगठन इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं यह भी माना जा रहा है कि नवीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार की नीयत सही है. 'किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020' का भाव यह है कि मध्यस्थों से बचाकर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, लेकिन इस संबंध में संशय यह है कि मंडी शुल्क से मुक्त होने के कारण व्यापारियों और कंपनियों को स्वाभाविक रूप से मंडी से बाहर खरीद के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सो मंडी का महत्व ही नहीं रहेगा. किसान भी मंडी से बाहर बिक्री के लिए बाध्य होगा. ऐसे में बड़ी खरीदार कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती हैं. कई लोगों का यह भी मानना है कि जब कानून बन ही रहे हैं और मंडी के बाहर खरीद को अनुमति दी जा रही है, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो और उससे कम पर खरीद गैर-कानूनी घोषित हो. यह भी कहा जा रहा है कि गैर कृषि औद्योगिक उत्पादों को कंपनियां स्वयं द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) पर बेचती हैं, जो उनकी उत्पादन लागत से कहीं ज्यादा होती है. ऐसे में किसानों को कम से कम अपनी लागत आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपना उत्पाद बेचने की सुविधा होनी चाहिए. चूंकि किसान की सौदेबाजी की क्षमता बहुत कम होती है, उसके लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए. नये प्रावधानों के अनुसार जब कोई खरीदार अपना पैन कार्ड दिखा कर किसान से खरीद कर सकता है, तो किसानों के उत्पाद का भुगतान भी तुरंत होना चाहिए या सरकार को उसके भुगतान की गारंटी लेनी चाहिए. किसान के पास अपनी उपज की बिक्री के लिए कई विकल्प होने चाहिए. यदि किसी बड़ी कंपनी या कुछ कंपनियों का प्रभुत्व हो जायेगा, तो गरीब किसान की सौदेबाजी की शक्ति समाप्त हो जायेगी. सरकार द्वारा पूर्व में 22 हजार मंडियों की स्थापना की बात कही गयी थी. इसे यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, ताकि किसान के पास अपनी उपज को बेचने के लिए अधिक विकल्प हों।

सार समाचार .....

इंटरनेशनल चैस में हिमाचल चैंपियन, छह देशों की प्रतियोगिता में प्रदेश को सबसे ज्यादा 531 अंक

मंडी , एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान झटका है। प्रदेश की टीम ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन स्पर्धा में 531 अंक प्राप्त करके देश व प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। प्रदेश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्पर्धा का आयोजन पहली बार जिला मंडी शतरंज संघ द्वारा किया गया। इस बाबत संघ के चीफ आर्बिटर राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में छह देशों के 137 खिलाड़ियों ने शिरकत की। यह प्रतियोगिता रैपिड फॉर्मेट में खेली गई। इसमें गेम के लिए दस से 12 मिनट (रैपिड फॉर्मेट) निर्धारित किए गए थे। स्पर्धा में भारत, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील व इटली के खिलाड़ियों ने भाग लिया। संघ के सहसचिव व विश्व रिकार्ड होल्डर चैस मैराथन हंसराज ठाकुर ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में हिमाचल के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 531 अंकों के साथ प्रथम स्थान, भारत के महाराष्ट्र की टीम ने 322 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर व तीसर, चौथे, सातवें, आठवें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम रही, जबकि पांचवे स्थान पर जर्मनी, छठे स्थान पर अर्जेंटीना, नौवें स्थान पर ब्राजील तथा दसवें स्थान इटली की टीम ने अर्जित किया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के अर्नव शर्मा ने सर्वाधिक 52 अंक अर्जित कर प्रदेश की टीम को बढ़त दिलाई। प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष जीत राम ठाकुर, सचिव देशराज शर्मा, उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने खुशी जताई है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों व शतरंज प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। संघ के सह सचिव व विश्व रिकार्ड होल्डर चैस मैराथन हंस राज ठाकुर ने बताया कि पिछले दो सालों में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में भी शतरंज काफी लोकप्रिय हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने शतरंज को शिक्षा विभाग में कक्षा एक से 12 तक की स्कूली खेलों में अनिवार्य रूप से शामिल किया है। उन्होंने बताया कि जिला मंडी शतरंज संघ का प्रदेश में शतरंज खेल को बढ़ावा देने के अग्रणी योगदान रहा है। संघ को पूर्ण उम्मीद है कि प्रदेश सरकार शतरंज खिलाड़ियों को प्रदेश के अंदर ही आवश्यक सुविधाओं को जल्द ही मुहैया करवाएगी।'

किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल बोले, गलतियों से लेंगे सीख

दुबई , एजेंसी। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में मिली 10 विकेट से हार के बाद कहा कि उनकी टीम योजनाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी। लोकेश ने कहा कि लगातार कई मैच हारना काफी दुखद है। हमें निरंतर प्रयास कर बेहतर वापसी करनी होगी। हम कहां गलती कर रहे हैं उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपनी योजनाओं को अच्छे से लागू नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम फाफ और वॉटसन के विकेट नहीं लेंगे तो जाहिर है हमें संघर्ष करना होगा। जब आप सात-आठ रन प्रति ओवर देते हो तो मैच में आक्रमण होकर विकेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत में 10 रन प्रति ओवर दे रहे थे इसलिए आक्रामक होना मुश्किल है। हमारे सभी खिलाड़ी काफी पेशेवर हैं और उम्मीद है हम जल्द ही वापसी करेंगे। चेन्नई के खिलाफ मिली हार के बाद पंजाब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम ने अब तक खेले पांच मैचों में से चार मैच गंवाकर अंकतालिका में आखिरी पायदान पर पहुंच गई है।

आई.पी.एल. में रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी जीत

आईपीएल के 13वें सीजन के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को 59 रन से हरा दिया। यह आईपीएल में बेंगलुरु के खिलाफ दिल्ली की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले दिल्ली ने आरसीबी को 2010 में 37 रन से हराया था। इस जीत के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है।

दुबई | एजेंसी।

मार्कस स्टोइनिस (53) और कगिसो रबाडा (4 विकेट) जीत के हीरो रहे। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली ने 197 रन का टारगेट दिया। जवाब में बेंगलुरु 9 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। रबाडा के अलावा दिल्ली के लिए एनरिच नोर्तजे ने 2 विकेट लिए।

पावर-प्ले में बेंगलुरु ने 3 विकेट गंवाए

टारगेट का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 3 विकेट पावर-प्ले में ही गंवा दिए। ओपनर देवदत्त पडिक्कल (4) और एरॉन फिंच (13) कुछ खास नहीं कर सके। पडिक्कल को रविचंद्रन अश्विन ने आउट किया। इसके बाद एरॉन फिंच भी अक्षर पटेल की बॉल पर ऋषभ पंत को कैच दे बैठे। इसके बाद एबी डिविलियर्स 9 रन बनाकर एनरिच नोर्तजे की बॉल पर आउट हुए।

अश्विन-अक्षर की सधी हुई गेंदबाजी दिल्ली के अनुभवी स्पिनर अश्विन और अक्षर ने सधी हुई गेंदबाजी की। दोनों के 8 ओवरों में बेंगलुरु की टीम सिर्फ 44 रन ही बना पाई। अक्षर ने 4.50 की इकोनॉमी से 18 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं, अश्विन ने 6.50 की इकोनॉमी से 26 रन देकर एक विकेट लिया।

दिल्ली ने बनाए 4 विकेट पर 196 रन

इससे पहले दिल्ली ने 4 विकेट पर 196 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 53 रन की नाबाद पारी खेली। यह आईपीएल में उनकी तीसरी फिफ्टी रही। इसके अलावा ऋषभ पंत ने भी 37 रन का योगदान दिया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 89 रन की पार्टनरशिप हुई। वहीं, बेंगलुरु के मोहम्मद सिराज को 2 जबकि इसुरु उडाना और मोइन अली को 1-1 विकेट मिला। **धवन-पृथ्वी के बीच 68 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप** दिल्ली के ओपनर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। शॉ ने 23 बॉल पर 42 रन बनाए। उन्हें मोहम्मद सिराज ने आउट किया। इसके बाद शिखर धवन (32) को इसुरु उडाना ने मोइन अली के हाथों कैच कराया। कप्तान श्रेयस अय्यर 11 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मोइन अली ने आउट किया। देवदत्त पडिक्कल ने बाउंड्री पर उनका शानदार कैच पकड़ा।

कोहली ने कोरोना नियम तोड़ा मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना नियम भी तोड़ा। दिल्ली की पारी के तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर फील्डिंग के दौरान उन्होंने बॉल पर लार लगा दी थी। इसके तुरंत बाद उन्हें अपनी गलती एहसास भी हुआ। यह वाकया कैमरे में कैद हो गया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के रॉबिन उथप्पा ने भी कोरोना नियम तोड़ा था। कोरोना के कारण ने आईसीसी ने बॉल पर लार लगाना बैन किया है। हर पारी में टीम को लार लगाने पर दो बार वार्निंग दी जाती है। तीसरी बार में जुर्माने के तौर पर विपक्षी टीम के खाते में 5 रन जोड़ दिए जाते हैं।

कोहली के नाम दो रिकॉर्ड इस मैच के साथ कोहली एक टीम के लिए सबसे ज्यादा टी-20 खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 197 मैच खेले। उन्होंने समरसेट के लिए 196 मैच खेलने वाले जेम्स हिल्ड्रेथ का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं, कोहली ओवरऑल टी-20 क्रिकेट में 9 हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय भी बने।

सबसे महंगे और सस्ते प्लेयर्स की परफॉर्मेंस

आरसीबी में कप्तान विराट कोहली सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। फ्रेंचाइजी उन्हें एक सीजन के 17 करोड़ रुपए देगी। उन्होंने मैच में 39 बॉल पर 43 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। प्लेइंग इलेवन में 20 लाख रुपए कीमत के साथ देवदत्त पडिक्कल सबसे सस्ते प्लेयर रहे। उन्होंने 6 बॉल पर 4 रन बनाए।

वहीं, दिल्ली में ऋषभ पंत 15 करोड़ रुपए कीमत के साथ सबसे महंगे प्लेयर रहे। उन्होंने 25 बॉल पर 37 रन की पारी खेली। टीम में हर्षल पटेल 20 लाख रुपए कीमत के साथ सबसे सस्ते रहे। वे 4 ओवर में 43 रन देकर कोई विकेट नहीं ले सके।

दिल्ली अब तक फाइनल नहीं खेली, बेंगलुरु को भी खिताब का इंतजार दिल्ली अकेली ऐसी टीम है, जो अब तक फाइनल नहीं खेल सकी। हालांकि, दिल्ली टूर्नामेंट के शुरुआती दो सीजन (2008, 2009) में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। वहीं, आरसीबी ने 2009 में अनिल कुंबले और 2011 में डेनियल विटोरी की कप्तानी में फाइनल खेला था।

2016 में विराट की कप्तानी में भी टीम फाइनल में पहुंची। लेकिन हर बार टीम को हार ही मिली।

विराट कोहली ने इंग्लिश प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा एक टीम के लिए सबसे ज्यादा 197 टी-20 खेले

कोलकाता, एजेंसी।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। वे किसी लीग में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा 197 टी-20 खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि आईपीएल सीजन-13 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उतरते ही हासिल कर ली।

कोहली ने इंग्लैंड के क्लब समरसेट के लिए 196 मैच खेलने वाले जेम्स हिल्ड्रेथ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 189 मैच के साथ चौथे और सुरेश रैना 188 मैच के साथ 5वें नंबर पर काबिज हैं। **आईपीएल में कोहली के सबसे ज्यादा रन**

कोहली ने आईपीएल में आरसीबी के लिए 182 और चैम्पियंस लीग में 15 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा 5502 रन बनाए हैं। कोहली ने चैम्पियंस लीग के 15 मैच में 424 रन बनाए हैं।

चेन्नई के लिए धोनी ने सबसे ज्यादा 189 मैच खेले

धोनी ने आईपीएल में कुल 195 मैच खेले हैं। इसमें चेन्नई के लिए 165 और पुणे सुपरजॉइंट्स के लिए 30 मैच खेले हैं। धोनी ने चैम्पियंस लीग में चेन्नई के लिए 24 मुकाबले खेले हैं। इस लिहाज से उन्होंने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा 189 मैच खेले हैं। वहीं रैना ने भी चेन्नई के लिए 188 मैच खेले हैं।

कोहली टी-20 फॉर्मेट में 9 हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय बने

कोहली ओवरऑल टी-20 क्रिकेट में 9 हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि भी दिल्ली के खिलाफ मैच में हासिल की। मैच में उन्होंने 43 रन बनाए। इसी के साथ कोहली ने इंटरनेशनल, घरेलू और आईपीएल समेत सभी 286 टी-20 मैच में 41.05 की उनके बाद रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 333 टी-20 में 8818 रन बनाए हैं।

चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बोले छोटी-छोटी चीजों को सही किया सफलता मिली

दुबई, एजेंसी।

चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में मिली 10 विकेट से जीत के बाद कहा कि उन्होंने छोटी-छोटी चीजों को सही किया। धोनी ने कहा कि हमने छोटी-छोटी चीजों को दुरुस्त किया। हमें बल्लेबाजी में जिस शुरुआत की दरकार थी, उस तरह की शुरुआत हमने की। यहां अनुभव काफी महत्व रखाता है। यह केवल आक्रमक होना नहीं है। वॉटसन नेट पर गेंद को काफी अच्छी तरह से हिट कर रहे थे। आपको केवल पिच पर इसे दोहराना होता है। फाफ टीम के आगे आकर भूमिका निभाते हैं। वह गेंदबाजों को अपने लैप शॉट से भ्रमित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ्लेमिंग जिस सम्मान के हकदार हैं, वह सम्मान उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि टीम के चयन को लेकर मेरे और फ्लेमिंग के बीच बहस नहीं हुई। लेकिन यह बात हमारे और उनके बीच ही रहती है। गेंदबाजों ने योजना के अनुरूप अच्छी गेंदबाजी की।

दिल्ली कैपिटल्स ने निकाला रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर का दम

आईपीएल 2020 के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर को 59 रन से हरा दिया। सोमवार को हुए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 196 रन बनाए।

नोवाक जोकोविच और पेत्रा क्विटोवा फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में

पेरिस एजेंसी। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके 14वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी की, जबकि दो बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्विटोवा ने आठ साल बाद रोलां गैरां में अंतिम आठ में जगह बनाई। अपने 18वें ग्रैंडस्लैम खिताब की कवायद में लगे जोकोविच ने रूस के 15वें वरीय करेन खाचनोव को दो घंटे 23 मिनट तक चले मैच में 6-4, 6-3, 6-3 से हराया। यह रोलां गैरां पर उनकी कुल 72वीं जीत है और 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर उन्होंने नडाल के रविवार को बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी की। वह यहां लगातार 11वीं बार अंतिम आठ में पहुंचे हैं और इस तरह से ओपन युग में उन्होंने अपने रिकॉर्ड को नए मुकाम पर पहुंचाया। जोकोविच ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंटों में 47वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं और वह इस मामले में रोजर फेडरर (57) के बाद दूसरे स्थान पर हैं। वह अगले दौर में पाब्लो कारेनो बस्टा और डेनियल अल्टमेयर के बीच होने वाले चौथे दौर के मैच के विजेता से भिड़ेंगे। महिला वर्ग में चेक गणराज्य की सातवीं वरीयता प्राप्त क्विटोवा ने चीन की गैर वरीय झांग शुहाई को 6-2, 6-4 से हराया। यह पिछले आठ वर्षों में पहला अवसर है, जबकि क्विटोवा ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह सुरक्षित की। इससे पहले यह 30 वर्षीय खिलाड़ी 2012 में रोलां गैरा में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। झांग पहले सेट में जब 2-5 से पीछे चल रही थी तब उन्होंने मेडिकल टाइम आउट भी लिया था। क्विटोवा ने इस बीच कोर्ट फिलिप चैटरियर पर सर्द मौसम से बचने के लिए गुलाबी रंग का कोट ओढ़ लिया था।

चोटिल मिश्रा-भुवी आईपीएल से बाहर, हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका

नई दिल्ली , एजेंसी। दिल्ली कैपिटल के सीनियर लेग स्पिनर अमित मिश्रा और सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस सीजन के बचे हुए मैचों में नहीं खेल सकेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के भुवी आईपीएल के बाद इस साल के अंत में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी बाहर हो सकते हैं। भुवी चोट के चलते मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में नहीं खेल सके थे। वहीं, अमित मिश्रा की रिंग फिंगर में चोट आई थी, जबकि दो अक्तूबर को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ मैच के दौरान भुवी को मसल इंजरी हुई थी। 37 वर्षीय अमित मिश्रा के खाते में 160 आईपीएल विकेट हैं और वह आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। दिल्ली कैपिटल्स अमित मिश्रा की इंजरी को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर चुका है। भुवी की इंजरी को लेकर अभी पिक्चर साफ नहीं है, लेकिन वह छह से आठ सप्ताह तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि भुवनेश्वर कुमार मसल इंजरी के चलते आईपीएल के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए हैं। यह ग्रेड दो या तीन की इंजरी है, इसका मतलब उनको सही होने में छह से आठ सप्ताह लग सकते हैं।

यशस्विनी सिंह ने ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल

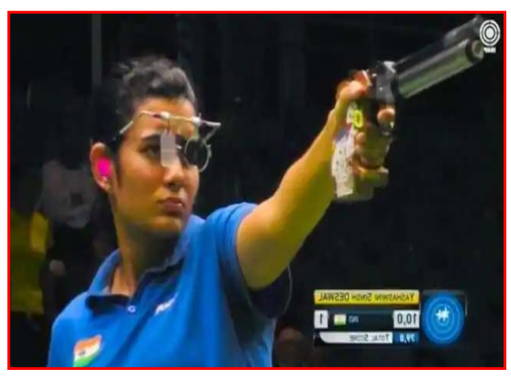

नई दिल्ली | एजेंसी।

विश्व की चौथे नंबर की निशानेबाज यशस्विनी सिंह देशवाल ने पांचवीं अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन इंडियाशूटिंगडॉटकाम ने किया था।

टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी यशस्विनी ने 241.7 अंकों के साथ खिताब जीता। पिछले वर्ष रियो डि जेनेरो में आईएसएसएफ विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली यशस्विनी ने क्वालिफिकेशन में 577 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। फाइनल में यशस्विनी ने पहले 10 शॉट के बाद शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी और उसके बाद लगातार दूसरा खिताब जीतने के लिए खेल पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। इससे पहले उन्होंने मई में हुए आईओएससी के चौथे संस्करण में गोल्ड मेडल जीता था। मिस्र की अहमद नबील दूसरे स्थान पर रहीं जबकि उनकी हमवतन येहया शम्स तीसरे स्थान पर रहीं।

नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थीम और पेत्रा क्विटोवा क्वार्टरफाइनल में पहुंचे

पेरिस , एजेंसी। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच, गत उपविजेता और यूएस ओपन चैंपियन ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम, पांचवीं सीड यूनान के स्तेफ़ानोस सितसिपास, सातवीं सीड चेक गणराज्य के पेत्रा क्विटोवा और 13वीं सीड रूस के आंद्रेई रुब्लेव ने अपने अपने मुकाबले जीतकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया। टॉप सीड और खिताब के प्रबल दावेदार जोकोविच ने सोमवार को चौथे दौर के मुकाबले में 15वीं सीड रूस के करेन खाचानोव को दो घंटे 23 मिनट में 6-4, 6-3, 6-3 से पराजित कर लगातार 11वें साल फ्रेंच ओपन के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली। यह लगातार दूसरा साल है जब जोकोविच बिना कोई सेट गंवाए अंतिम आठ में पहुंचे हैं। जोकोविच का इस साल 35-1 का रिकॉर्ड हो गया है। तीसरी सीड थीम ने विश्व के 239वें नंबर के खिलाड़ी ह्यूगो गास्टन को रविवार को पांच सेटों के संघर्ष में हराया। थिएम ने तीन घंटे 32 मिनट तक चले मुकाबले में गास्टन को 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। इस साल अमेरिकी ओपन का खिताब जीतने वाले थीम का मुकाबला अब 12वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्समैन से होगा। श्वार्ट्समैन ने चौथे दौर में फ्रांस के लोरेंजो सोनगो को लगातार सेटों में 6-1, 6-3, 6-4 से हराया। गास्टन ने पिछले दौर में पूर्व चैम्पियन स्विटरजरलैंड के स्टेनिस्लास वावरिंका को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। लेकिन इस लय को वह चौथे दौर में बरकरार नहीं रख पाए। पांचवीं सीड सितसिपास ने 18वीं सीड बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को सोमवार को दो घंटे 26 मिनट में 6-3, 7-6 (9), 6-2 से हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली। सितसिपास का सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए रूसी खिलाड़ी रुब्लेव से मुकाबला होगा जिन्होंने चौथे दौर के एक अन्य मैच में हंगरी के मार्क्स फुकसोविक्स को 6-7(4), 7-5, 6-4, 7-6 (3) से हराया।

शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी के लिए एक-दो नहीं, पूरे 8 करोड़ रुपये सैलरी कट

कोविड ने दुनिया भर के हालात को बदल दिया है और इसका असर फिल्म इंडस्ट्री पर भी खूब पड़ा है। ऐसे में खबर है कि शाहिद खान ने अपनी अगली फिल्म जर्सी के लिए अपनी फीस कम कर दी है।

जहां कई फिल्ममेकर्स और फिल्मों को कोरोना की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है, वहां इंडस्ट्री की लगभग तमाम कंपनियों के कोविड की वजह से सुरक्षा नियमों का पालन और सेट पर इससे जुड़ी बाकी चीजों का ध्यान रखने के लिए खर्च में इजाफा हुआ है। ऐसे में शाहिद खान अपनी सैलरी में कटौती कर मेकर्स के लिए इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आगे आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद ने अपनी फिल्म जर्सी को दो कंडिशन पर साइन किया था, जिसमें से एक तो 33 करोड़ रुपये फीस थी और दूसरा प्रॉफिट में शेयर की भी बात थी। मेकर्स फिल्म स्टार्स की मांग को लेकर तैयार भी हो गए थे और फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर दी गई। हालांकि, कोविड ने सारी परिस्थितियां बदल दीं और नौबत ये आ गई कि मेकर्स को अपने स्टार से फीस कम करने की गुजारिश करनी पड़ गई।

खबर है कि शाहिद कपूर ने अपनी इस फिल्म मेकर्स की मजबूरियों को समझा और अपनी फीस में से 8 करोड़ उन्होंने कम कर दिए। अब वह अपनी फिल्म जर्सी के लिए केवल 25 करोड़ रुपये लेंगे। कहा जा रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग वाली शर्तों को मेकर्स ने यूं ही बरकरार रखा है।

तापसी पन्नू की फिल्म एनाबेल की शूटिंग पूरी अभिनेत्री ने दिया हिंट

बॉलीवुड की मशहूर और शानदार अभिनेत्री तापसी पन्नू पिछले काफी समय से से अपनी एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी। उनकी फिल्म का नाम एनाबेल है जिसकी शूटिंग वो पिछले कई दिनों से जयपुर में कर रही थी। हालांकि अब तापसी पन्नू की फिल्म एनाबेल की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अभिनेत्री अब अपने घर वापस आ चुकी है। फिल्म की शूटिंग की जानकारी खुद अभिनेत्री ने दी है। जी हां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में तापसी पन्नू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की है

जिसमे उन्होंने बताया है कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करके काफी खुश है। इसी के साथ उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की है उसके जयपुर की झलक साफ देखने को मिल रही है। तापसी पन्नू पिंक कारपेट पर पहाड़ों की ओर मुंह किए बैठी नजर आ रही हैं।

अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए तापसी पन्नू ने कैप्शन में लिखा कि, कुछ महीनों पहले यह सब एक सपना लगता था और अब यह रैप है। साथ ही तापसी पन्नू ने बताया कि उनकी फिल्म एनाबेल को गुड बॉय बोलने का समय आ गया है। एनाबेल तापसी पन्नू की ये फिल्म साउथ की फिल्म है जिसको कई भाषा में रिलीज करने का मेकर्स का प्लान है। फिल्म के सेट से तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने इशारा किया है कि फिल्म थिएटर पर रिलीज होगी। इसका मतलब ये तय है कि फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगर हम बात करें तापसी पन्नू बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में नजर आने वाली है।

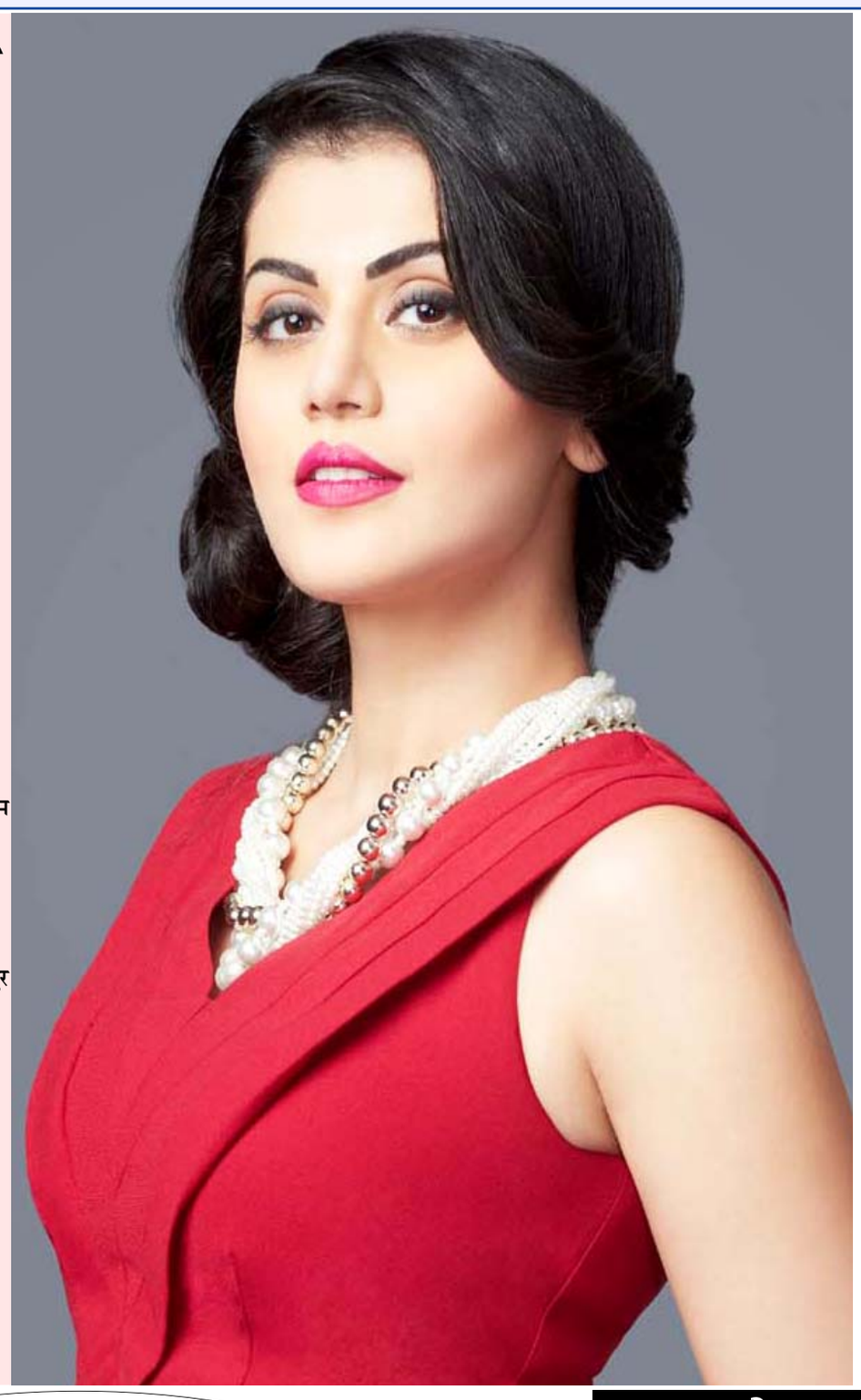

फिल्म वेक अप सिड' के 11 साल पूरे नमित दास ने याद किया

फिल्म वेक अप सिड' को शुक्रवार को रिलीज हुए 11 साल हो गए, जिसपर बॉलीवुड अभिनेता नमित दास ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह फिल्म इतनी प्रसिद्धी हासिल कर लेगी। दास ने फिल्म को याद करते हुए कहा, मेरे लिए यह बहुत अच्छी बात है कि मैंने इस फिल्म से अपने करियर की शुरूआत की। जब मुझसे पहली बार इसके लिए संपर्क किया गया तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि यह आगे जाकर एक प्रसिद्ध फिल्म बनेगी। हालांकि मुझे पता था कि यह एक विशेष और अनोखी फिल्म है। मुझे लगा कि मैं अपने किरदार ऋषि से कुछ बना सकता हूं। यह वास्तव में अयान का उत्साह और सकारात्मकता ही थी जिसने मुझे इस परियोजना की ओर आकर्षित किया। अभिनेता के आगामी परियोजना की बात करें तो, उन्हें फिल्म आफत-ए-इश्क', और मीरा नायर की फिल्म ए सुटेबल बॉय' में देखा जाएगा।

आ गया बेल बॉटम का टीजर, धांसू है अक्षय कुमार का लुक

पिछले काफी दिनों से अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म बेल बॉटम चर्चा में है। हाल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी हुई है और अब मेकर्स ने इसका टीजर भी रिलीज कर दिया है। अक्षय कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है। फिल्म में अक्षय कुमार 80 के दशक के रेट्रो लुक में गजब के दिख रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वाणी कपूर लीड रोल में है। इनके अलावा हुमा कुरैशी और लारा दत्ताभी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। यह एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार के लुक की चर्चा पिछले काफी दिनों से चल रही है। फिल्म में अक्षय कुमार कई अलग-अलग लुक्स में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग स्कॉटलैंड में की गई है और बहुत जल्दी खत्म की गई है।

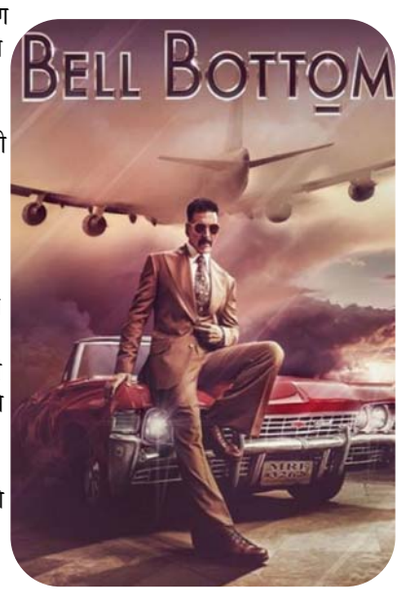

रंजीत एम तिवारी के डायरेक्शन में बनी बेल बॉटम को वासु भगनानी, जैकी भगनानी, दीपशिखा देशमुख, मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल आडवाणी ने प्रड्यूसर किया है। इस फिल्म को अगले साल यानी 2 अप्रैल 2021 को रिलीज किए जाने की योजना है।

कातिलाना अंदाज में हिना खान ने बरपाया कहर, कुछ इस अंदाज में दिए पोज

छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर पहचान बनाने वाली हिना खान अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस की काफी फैन फॉलोइंग है। इस वजह से उनकी तसवीरें सोशल साइट्स पर आते ही वायरल हो जाती है। हाल ही में हिना ने अपनी बेहद खूबसूरत तसवीरें शेयर की है, जिसे देख फैंस उनके दीवाने हो रहे हैं। लुक की बात करें तो इस दौरान एक्ट्रेस पोल्का डॉट ड्रेस में कहर बरपा रही हैं। स्लीवलेस टॉप को एक्ट्रेस ने मैचिंग लूज पैंट के साथ टीम-अप किया है और साथ ही येलो कलर की हील पेयर की हुई हैं। न्यूड मेकअप और ओपन हेयर्स एक्ट्रेस के लुक को कम्पलीट कर रहे हैं। खूबसूरत लुक को कैरी करते हुए हसीना कैमरे के सामने एक से बढ़ कर एक परफेक्ट पोज दे रही हैं। एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देख फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। काम की बात करें तो हिना ने अपने करियर की शुरूआत टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से की थी, जिसमें उन्हें संस्कारी बहू के किरदार से खूब पॉपूलेरिटी मिली। कसौटी जिंदगी के की कमोलिका के रोल में भी एक्ट्रेस ने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया था।टीवी शो के अलावा एक्ट्रेस फिल्म हैक्ड में भी नजर आ चुकी हैं।

नए वेब सीरीज में ड्रग एडिक्ट का किरदार निभाएंगे अक्षय ओबेरॉय

अभिनेता अक्षय ओबेरॉय अपनी आने वाली वेब सीरीज में एक ड्रग एडिक्ट के किरदार में नजर आएंगे। इसका शीर्षक हाई' है। अक्षय ने कहा, इसे स्क्रीन पर दिखाना इतना आसान नहीं था। नशा कुछ ऐसा है, जिसमें लोगों का अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता है, अच्छे लोग भी इसमें आकर अजीब ढंग से बर्ताव करने लगते हैं। दर्शक इससे खुद को आसानी से नहीं जोड़ पाते हैं और न ही इसमें उनकी कोई सहानुभूति रहती है। कहानी में अपने किरदार पर मैंने काफी शोध किया कि यह किन परिस्थितियों में से जाएगा, इसके किस तरह के एहसास होंगे। इस विषय पर मैंने कई लेख भी पढ़े हैं, फिल्में देखी है ताकि फिल्मों में समय दर समय इस विषय पर हुए विकास पर गौर फरमा सकूं। इनसे मुझे विषय को समझने और अपनी कल्पनाओं को यथासंभव वास्तविक रूप देने में मदद मिली है।

निखिल राव द्वारा निर्देशित हाई' में शिव माथुर की जिंदगी के बारे में दिखाई जाएगी, जो ड्रग की समस्या से इस कदर परेशान है कि अपनी निजी जिंदगी में सामंजस्य बिठाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए वह एक रिहैब सेंटर में जाता है, जहां का माहौल काफी रहस्यमयी मालूम पड़ता है।

कंगना ने शुरू की फिल्म थलाइवी की शूटिंग सोशल मीडिया पर शेयर किया ये पोस्ट

बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक कंगना रानौत पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है वही हर दिन किसी ना किसी विवाद के चलते खबरों में रहती है। हलाकि की पिछले कुछ दिनों से कंगना काफी ज्यादा शांत नजर आ रही है। एक लम्बे इंतजार के बाद कंगना अपने काम पर लौट आई है जिसको लेकर वह काफी ज्यादा उत्साहित है। कुछ दिनों पहले कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था की वह फिल्म थलाइवी की शूटिंग पर लौट रही है। अब इस फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरे सामने आई है। जिसको देख कर साफ लग रहा है की कंगना किस तरह अपने काम को गंभीरता से ले रही है। कंगना की इस फिल्म का निर्देशन एएल विजय कर रहे है। कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्विट करते हुए लिखा - % गुड मोर्निंग दोस्तों, ये कल के शूट की कुछ तस्वीरे है जब में बहुत ही प्रतिभाशाली निर्देशक एएल विजय के साथ सीन को डिस्कस कर रही हूं। उन्होंने आगे लिखा फिल्म का सेट मुझे सबसे ज्यादा सुकून देता है। वही कंगना ने कुछ तस्वीरे भी शेयर की है जिसमे वह काफी खूबसूरत नजर आ रही है।

हनीमून की वजह से चर्चा में आईं थी इस सुपरस्टार की बहू रियल लाइफ में है काफी बोल्ड

साउथ सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य और उनकी पत्नी एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। समांथा हमेशा ही अपनी बोल्ड और खूबसूरत तस्वीरों की वजह से चर्चा में रहती हैं। वह अक्सर अपने पति नागा चैतन्य के साथ अपनी हॉट फोटोज शेयर करती हैं। आज समांथा और नागा चैतन्य की मैरिज एनिवर्सरी है। क्या आप जानते हैं समांथा और नागा चैतन्य ने 40 दिनों तक हनीमून मनाया था। आज हम इस खास मौके पर दोनों की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चहिए जानते हैं... नागा चैतन्य और समांथा रुथ प्रभु ने 7 अक्टूबर, 2017 का शादी की थी। शादी के बाद दोनों की कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सामने आईं थी। आपको बता दें कि शादी के बाद समांथा और नागा चैतन्य ने 40 दिनों तक हनीमून मनाया था। इस बात को लेकर वह काफी चर्चा में रही थीं। दोनों की लव स्टोरी की बात करें तो वो उनकी पहली मुलाकात फिल्म ये माया चेस्वे के सेट पर 2009 में हुई थी। हालांकि, उस दौरान चैतन्य, एक्ट्रेस श्रुति हासन को पसंद करते थे। तो वहीं समांथा, एक्टर सिद्धार्थ को पसंद करती थीं। लेकिन फिर साल

2015 में दोनों फिल्म ऑटोनगर सूर्या में दोनों करीब आए। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। नागा चैतन्य और समांथा रुथ प्रभु ने 7 अक्टूबर 2017 का शादी की थी। शादी के बाद दोनों की कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सामने आईं थी। आपको बता दें कि शादी के बाद समांथा और नागा चैतन्य ने 40 दिनों तक हनीमून मनाया था। साउथ सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य और उनकी पत्नी एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। समांथा हमेशा ही अपनी बोल्ड और खूबसूरत तस्वीरों की वजह से चर्चा में रहती हैं। वह अक्सर अपने पति नागा चैतन्य के साथ अपनी हॉट फोटोज शेयर करती हैं। आज समांथा और नागा चैतन्य की मैरिज एनिवर्सरी है। क्या आप जानते हैं समांथा और नागा चैतन्य ने 40 दिनों तक हनीमून मनाया था। आज हम इस खास मौके पर दोनों की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। नागा चैतन्य और समांथा रुथ प्रभु ने 7 अक्टूबर, 2017 का शादी की थी। शादी के बाद दोनों की कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सामने आईं थी। आपको बता दें कि शादी के बाद समांथा और नागा चैतन्य ने 40 दिनों तक हनीमून मनाया था। इस बात को लेकर वह काफी चर्चा में रही थीं। दोनों की लव स्टोरी की बात करें तो वो उनकी पहली मुलाकात फिल्म ये माया चेस्वे के सेट पर 2009 में हुई थी।

कंचन उजाला हिंदी दैनिक

स्वामी नमोकंचन कार्पोरेट सर्विसेस (एल.एल.पी) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कंचन सोलंकी द्वारा उमाकान्ती ऑफसेट प्रेस, ग्राम डेहवा पोस्ट मोहनलाल गंज लखनऊ से मुद्रित एवं 61/18 चुटकी भण्डार हुसैनगंज लखनऊ से प्रकाशित।

संपादक- कंचन सोलंकी

TITLE CODE- UPHIN48974

Mob: 8896925119, 9695670357
Email: kanchansolanki397@gmail.com

नोटः समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारो एवं लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नही। समस्त विवादो का निस्तारण लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।